राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत–गुजरात,संस्करण बुधवार,02जून–2021 वर्ष–4, अंक –129पृष्ठ–08 मूल्य–01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

### 24 घंटे चल रहा है राम मंदिर का निर्माण कार्य

**अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा नींव का काम, तीन साल में बन जाएगा मंदिर-चंपत राय**

राम मंदिर का निर्माण कार्य 24 घंटे जारी है। यह 12-12 घंटे की दो पालियों में हो रहा है। अभी तक 1.2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में खुदाई का काम हो गया है। हमें उम्मीद है कि यह काम अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा।

**नई दिल्ली।** अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर-शोर से चल रहा है और इसका एक हिस्सा इसी साल अक्टूबर में बनकर तैयार हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इस बारे में जानकारी दी है। चंपत राय ने बताया कि इस साल अक्टूबर में मंदिर की नींव का काम पूरा हो जाएगा।

उन्होंने बताया, राम मंदिर का निर्माण कार्य 24 घंटे जारी है। यह 12-12 घंटे की दो पालियों में हो रहा है। अभी तक 1.2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में खुदाई का काम हो गया है। हमें उम्मीद है कि यह काम (नींव बनाने का) अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। भगवान राम की कृपा से सभी मजदूर और इंजीनियर स्वस्थ हैं।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य की जिम्मेदारी है। राय ने इससे पहले आठ मार्च को कहा था कि राम मंदिर अगले तीन साल में बनकर तैयार हो जाएगा। राय ने उस समय यह भी कहा था कि राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में घर-घर जाकर मदद मांगने का अभियान कोरोना महामारी के कारण रोक दिया गया है लेकिन अगर किसी को मदद करनी है तो वह ट्रस्ट की वेबसाइट के जरिए कर सकता है।

# अब ब्लैक फंगस को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला

**नई दिल्ली।** देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी होने लगी है। हालांकि, कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब भी डरा रहा है. इस बीच विपक्ष की तरफ से कोरोना प्रबंधन और वैक्सीनेशन नीति को लेकर केन्द्र सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार निशाना साधा है। इस बार वे ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र से सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए केंद्र से 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा- ब्लैक फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट करे-

1. Amphotericin B दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है?

2. मरीज़ को ये दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है?

3. इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फँसा रही है?

इससे पहले सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार की शून्य टीका नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। उन्होंने

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में बेरोजगारी बढ़ने संबंधी खबर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।

कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर दावा किया था, 'मोदी सरकार की शून्य टीका नीति (ज़ीरो वैक्सीन पॉलिसी) भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। दुःखद सच।' बेरोजगारी दर के दहाई के आंकड़े में पहुंचने संबंधी एक खबर को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा, 'एक व्यक्ति और उसका अहंकार है, एक वायरस और उसके कई स्वरूप हैं।'

वहीं, कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में दावा किया था कि टीकाकरण की जो गति अभी चल रही है वह यदि इसी प्रकार चलती रही तो उसके पूरा होने में तीन साल लग जाएंगे। उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि प्रधानमंत्री की 'नौटंकी के कारण कोरोना की दूसरी लहर आई।

### भारत के वैक्सीन निर्यात रोकने से

# कोरोना के गंभीर खतरे में दुनिया के 91 देश-विश्व स्वास्थ्य संगठन

**नई दिल्ली।** भारत की ओर से दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाए जाने से 91 देशों को झटका लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत की ओर से एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से इन देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन के फैलने का खतरा बढ़ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक से खासतौर पर अफ्रीकी देशों को झटका लगा है। यहां क्र1.617.2 वैरिएंट के प्रसार का खतरा बढ़ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, दुनिया के 91 देशों में वैक्सीन की सप्लाई प्रभावित हुई है। खासतौर पर भारत से रोक के बाद एस्ट्राजेनेका की पेरेंट कंपनी की ओर से भरपाई न किए जाने के चलते ऐसा हुआ है। स्वामीनाथ ने कहा कि इन देशों में इस नए वैरिएंट के अलावा कोरोना के नए स्ट्रेंस का भी खतरा बढ़ा है। भारत की ओर से मध्यम और कम आय वर्ग वाले देशों को वैक्सीन की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन घरेलू स्तर पर केसों में तेजी से इजाफे के चलते इस मिशन को रोक दिया गया था। स्वामीनाथन का कहना है कि अफ्रीकी देशों के सामने कोरोना का खतरा ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि इन देशों की 0.5 फीसदी आबादी को भी कोरोना टीका नहीं लग सका है। यहां तक कि इस दायरे में सभी हेल्थकेयर वर्कर्स भी नहीं आ सके हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में इतना अंतर देखते हैं तो आने वाले दिनों में बड़ी गैरबराबरी नजर आएगी। एक तरफ कोरोना केसों में कमी के चलते कई देश वापस सामान्य जिंदगी में लौटते दिखेंगें तो वहीं कुछ देशों में कोरोना का भीषण कहर हो सकता है। इस बीच भारत

में ही वैक्सीन की खरीद को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। टीकों की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के तेजी से उभार के चलते कई देशों ने वैक्सीनों का निर्यात रोकते हुए पहले अपनी घरेलू आबादी के टीकाकरण को तेज करने का फैसला लिया है।

# दिल्ली सरकार ने देशी विदेशी शराब की होम डिलीवरी को दी मंजूरी

**नई दिल्ली।** दिल्ली सरकार ने देशी और विदेशी हर किस्म की शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए ऑर्डर मोबाइल एप या वेब पोर्टल के जरिए दिया जा सकता है। गौरतलब है कि अप्रैल में जब दिल्ली में लॉकडाउन लगा था तब शराब की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई थी उसी वक्त शराब की कंपनियों ने दिल्ली सरकार से शराब की होम डिलीवरी शुरू करने की मांग की थी। अनुमान है कि सरकार का ये फैसला उसी मांग के चलते आया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दुकानें बंद हैं। बावजूद सरकार ने होम डिलीवरी की अनुमति दी है। दिल्ली में अप्रैल में लॉकडाउन के बाद शराब बिक्री केंद्रों पर भीड़ बढ़ गई थी। यह जनता की घबराहट ही थी।

**अनुमान है कि सरकार का ये फैसला उसी मांग के चलते आया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दुकानें बंद हैं।**

एसोसिएशन ने उम्मीद जताई थी कि दिल्ली में ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए अप्रैल से लॉकडाउन लगा दिया गया था। इसकी घोषणा होते ही शराब ठेकों पर देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई इसी होड़ में लगा था कि किसी तरह जरूरत भर बोतलें मिल जाएं। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कोविड नियम तो दूर, लोग सोशल डिस्टेंसिंग तक को भूल गए। गोल मार्केट इलाके में तो भीड़ इतनी अधिक हो गई थी कि पुलिस को क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ गया था।

### देश के 26 राज्यों में फंगस

# 20 हजार मरीज उपचाराधीन, कुल मांग के दस फीसदी बराबर इंजेक्शन भी नहीं

**नई दिल्ली।** कोरोना महामारी के साथ देश के 26 राज्यों में ब्लैक फंगस की भी दस्तक हो चुकी है। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन की 30,100 वॉयल आवंटित की है। हालांकि ये वॉयल के कुल मांग का दस फीसदी भी नहीं है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया कि सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 30,100 एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की एक खेप दी गई है। देश में अभी करीब 20 हजार मरीज उपचाराधीन हैं जिनके लिए हर दिन 30 हजार वॉयल चाहिए। एक दिन में दो बार यह इंजेक्शन दिया जाता है और करीब छह सप्ताह तक ज्यादातर मामलो में देना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नागर हवेली, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,सिक्किम और नगालैंड को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंगस के मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। देश में अभी एक लाख इंजेक्शन की उत्पादन क्षमता है।

**सात राज्यों में सबसे अधिक मरीज**

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फंगस के रोगी उपचाराधीन हैं। इसीलिए यहां सबसे अधिक दवा आवंटित की गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार के अस्पतालों में भी काफी मरीजों का उपचार चल रहा है। इसीलिए सरकार ने इन अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए 1260 वॉयल आवंटित किए हैं।

**सोशल मीडिया पर छलका डॉक्टरों का दर्द**

ब्लैक फंगस से तड़पते मरीजों को समय पर दवा और इंजेक्शन न मिलने से डॉक्टरों की भी हिम्मत जवाब देने लगी है। बेंगलूरू के मणिपाल अस्पताल के डॉ. रघुरात हेगड़े ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ब्लैक फंगस से तड़पते मरीजों की जान बचाने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद जान नहीं बचा पा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि वे अब तक कई मरीजों की आंख निकाल चुके हैं।

**समय पर दवा मिलना मुश्किल हो रहा**

डॉ. रघुराजन का कहना है कि कुछ मरीजों में फंगस पहले ही काफी फैल चुका होता है। इसका कारण ऐसे मरीजों की जान मुश्किल में पड़ जाती है। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो शुरुआती लक्षण के साथ अस्पताल में भर्ती होते हैं लेकिन समय पर इंजेक्शन और दूसरी दवाएं न मिलने के कारण उनकी भी जान मुश्किल में पड़ रही है। यही कारण है कि फंगस के कारण देश में मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है।

## महाराष्ट्र के घरेलू हवाई यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं

### बीएमसी ने जारी किया आदेश

**मुंबई।** महाराष्ट्र के किसी भी हवाईअड्डे से मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब महाराष्ट्र के किसी भी इलाके से हवाई यात्रा के जरिए मुंबई आने पर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट साथ लाना जरूरी नहीं है। सोमवार को जारी किए एक आदेश में बीएमसी ने इस बात की जानकारी दी। बीएमसी ने एक आदेश में कहा कि अब से मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के लिए नहीं कह सकते। बीएमसी ने कहा कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। बता दें कि आरटी-पीसीआर के जरिए किसी भी शख्स के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चलता है। बीएमसी की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी घरेलू यात्री, जो महाराष्ट्र के किसी स्थान से हवाई यात्रा के जरिए मुंबई आ रहे हैं, उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य नहीं है। दिशा-निर्देशों में कहा गया कि सभी घरेलू हवाई यात्रियों को मुंबई से महाराष्ट्र के किसी भी कोने में हवाई यात्रा करने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के दैनिक मामले कम हो रहे हैं और इसके बावजूद सरकार ने वहां अभी भी सख्ती बनाई हुई है। इससे पहले मई महीने में यह आदेश आया था कि सभी घरेलू हवाई यात्रियों को मुंबई से हवाई यात्रा के जरिए महाराष्ट्र के किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य था। आदेश में कहा गया था कि मुंबई आने से पहले 48 घंटे पहले कोरोना की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट हो जानी चाहिए।

# पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी राज्यसभा के लिए मनोनीत

**नई दिल्ली।** जाने माने वकील महेश जेठमलानी ने कहा है कि उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की सूचना मिली है। जेठमलानी ने भाषा से कहा, मुझे राज्यसभा के लिए नामित किए जाने की सूचना दी गयी है। कई बड़े मामलों में पैरवी कर चुके उनके पिता एवं मशहूर वकील राम जेठमलानी भी राज्यसभा सदस्य थे। वे देश के कानून मंत्री रह चुके हैं। जेठमलानी को दिवंगत सांसद रघुनाथ महापात्रा के खाली हुए पद पर नामित सांसद की कैटेगरी में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। महापात्र का इसी माह कोविड-19 के कारण निधन हो गया।

**कई बड़े मामलों में पैरवी कर चुके उनके पिता एवं मशहूर वकील राम जेठमलानी भी राज्यसभा सदस्य थे। वे देश के कानून मंत्री रह चुके हैं। जेठमलानी को दिवंगत सांसद रघुनाथ महापात्रा के खाली हुए पद पर नामित सांसद की कैटेगरी में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। महापात्र का इसी माह कोविड-19 के कारण निधन हो गया।**

राज्यसभा सांसद के तौर पर जेठमलानी का कार्यकाल मई 2024 तक रहेगा। महेश जेठमलानी का नामांकन ऐसे वक्त में आया है जब हाल में नामित किए जाने की श्रेणी में दो रिक्तियां हुईं। स्वपन दासगुप्ता ने इस साल मार्च में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा ने उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा था। दूसरी रिक्ति तब हुई जब रघुनाथ महापात्र का इसी माह कोविड-19 के कारण निधन हो गया। बता दें कि राष्ट्रपति केंद्र के परामर्श पर राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये लोग साहित्य, विज्ञान, खेलकूद, कला एवं समाज सेवा जैसे क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां होते हैं। महेश जेठमलानी की गिनती देश के महंगे वकीलों में होती हैं। साल 2009 में उन्होंने प्रिया दत्त के खिलाफ लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए।

# कोरोनाः देश पर मंडरा रहा तीसरी लहर का खतरा

### आईसीएमआर ने चौथे सीरो-सर्वेक्षण की बनाई योजना

**नई दिल्ली।** देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है। वहीं तीसरी लहर के आने की आशंका बनी हुई है। इस बीच, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) देश में चौथा सीरो-सर्वेक्षण कराने की तैयारी में है। इससे पहले नौ माह में तीन-तीन बार सीरो सर्वे किए गए, जबकि फिलहाल पिछले चार माह से सीरो सर्वे नहीं हुआ है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महामारी विज्ञान और संचार रोग विभाग के प्रमुख डॉ.समीरन पांडा ने कहा, चौथे सीरो सर्वे कराने की योजना पर काम जारी है। आईसीएमआर के महानिदेशक की ओर से औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की जाएगी। डॉ. समीरन पांडा का कहना है कि सबसे पहले जिन जिलों में संक्रमण दर अधिक है, वहां बहुत तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें सीरो सर्वे भी मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि जनवरी में हुए सीरो सर्वे में एक चौथाई आबादी संक्रमण की चपेट में आने की पुष्टि हुई थी, लेकिन यह भी पता चला था कि 75 फीसदी आबादी संकट में है जिन्हें बचाव की सबसे ज्यादा जरूरत है।

**चार माह बाद सीरो सर्वे कराने पर चर्चा**-वर्तमान हालात देखें तो बीते चार माह से देश में एक भी सीरो सर्वे नहीं हुआ है, जबकि उससे पहले नौ माह में तीन-तीन बार सीरो सर्वे किया गया। इस सर्वे के दौरान गांव-गांव जाकर लोगों के रक्त नमूने लेकर जांच की गई तो कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी का पता चला। वहीं आंकड़ों के अनुसार, इसी साल एक मार्च से अब तक देश में एक करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जबकि जनवरी, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक 1.11 करोड़ मामले थे और 1.57 लाख लोगों की मौत हुई थी।

**फैल गया कोरोना, अब सीरो सर्वे का लाभ नहीं**-आईसीएमआर के ही एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि दूसरी लहर में कोरोना गांव-गांव तक पहुंच चुका है। उन्हें नहीं लगता कि अब सीरो सर्वे का कोई फायदा होगा क्योंकि उसके परिणाम पहले से ही हमें पता है। हालांकि, टीकाकरण को लेकर सर्वे की जरूरत है ताकि यह पता चले कि कितनी फीसदी आबादी सुरक्षा जोन में है। इस पर विचार भी चल रहा है लेकिन अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।

**गणितीय आकलन के लिए सर्वे जरूरी**-यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की प्रो. भ्रामक मुखर्जी के अनुसार भारत में अभी 2.47 करोड़ से ज्यादा मामले हैं, लेकिन उनका अनुमान है कि यह संख्या 49 करोड़ से ज्यादा है जोकि 36 फीसदी आबादी के संक्रमित होने का इशारा करता है। भारत में नौ में से करीब दो मौतें ही कागजों पर दर्ज की जा रही हैं। हमारे इस अनुमान को साबित करने के लिए सीरो सर्वे का होना बहुत जरूरी है। महामारी में गणितीय आकलन को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसके आधार पर भविष्य की नीतियां तय होने में मदद मिलती है।

**इससे पहले कब-कब हुए सीरो सर्वे**

- **पहला सर्वे**- मई से जून 2020 के दौरान किए इस सर्वे में 0.73 फीसदी आबादी में एंटीबॉडी मिलीं।
- **दूसरा सर्वे**-अगस्त से सितंबर 2020 के दौरान 6.6 फीसदी आबादी संक्रमण की चपेट में।
- **तीसरा सर्वे**-दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के दौरान 21.4 फीसदी आबादी में संक्रमण।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

## निर्माण को हरी झंडी

दल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम पर फिलहाल रोक लगाने के लिए दायर एक जनहित याचिका ठुकरा दी है। इस याचिका में यह कहा गया था कि चूंकि फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर के चलते इस परियोजना पर काम का चलते रहना, उसमें काम करने वाले मजदूरों और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और इससे कोरोना फैल सकता है। सरकार का दावा था कि वहां काम करने वाले मजदूरों को टीके लगाए जा चुके हैं और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है। सरकार का यह भी कहना था कि यह याचिका सिर्फ सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम में अड़ंगा डालने के नजरिए से लाई गई है। बहरहाल, इस याचिका पर फैसला होना सांकेतिक जीत-हार जैसा ही है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में ढील दे दी है और दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर से रोक हट गई है। सेंट्रल विस्टा परियोजना पर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी काम जारी रखने के लिए सरकार ने उसे आवश्यक सेवाओं में शामिल कर दिया था। इस बात के लिए सरकार की भारी आलोचना भी हुई थी। आलोचना का आधार यह था कि जब कोरोना ने देश को हिलाकर रख दिया है, तब इस परियोजना पर संसाधन नहीं खर्च किए जाने चाहिए। आलोचना करने वालों का कहना यह भी था कि आखिर इस परियोजना में इतना महत्वपूर्ण क्या है, जो इसे आवश्यक सेवा घोषित किया गया? सरकार का कहना यह है कि सेंट्रल विस्टा के सिर्फ उन हिस्सों पर काम चल रहा है, जिन्हें पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी और जिनके मद में पैसा आवंटित किया जा चुका था। यह काम और यह राशि पूरी सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक छोटा हिस्सा है, इसलिए इससे कोई बड़ा आर्थिक भार सरकारी खजाने पर नहीं पड़ने वाला। सरकार का के इस तर्क को भी अदालत ने मान लिया कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है, क्योंकि इन इमारतों में हमारे गणतंत्र से जुड़े विधायी काम होने हैं। इस नजरिए से भी यह जरूरी है कि ठेकेदार शापूरजी पालनजी ग्रुप ठेके में दर्ज तारीखों तक अपना काम पूरा कर सके। राजपथ पर निर्माण कार्य का नवंबर तक पूरा होना इसलिए भी जरूरी है कि जनवरी में गणतंत्र दिवस की परेड यहां आयोजित की जा सके। अदालत में इस याचिका पर बहस के दौरान काफी तीखे आरोप-प्रत्यारोप हुए। याचिकाकर्ताओं ने परियोजना पर काम करने वाले मजदूरों की स्थिति की तुलना नाजी जर्मनी के ऑशविट्ज यातना शिविरों से की, तो सरकार ने यह आरोप लगाया कि यह जनहित याचिका की आड़ में परियोजना रोकने की कोशिश है और इसलिए याचिकाकर्ताओं को ऐसा दंड मिलना चाहिए, जो सबक सिखा सके। अदालत ने सरकार के पक्ष को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह याचिका और इससे जुड़ा विवाद सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर चल रहे विवाद का एक अध्याय है। इस विवाद के एक पक्ष में सरकार और उसके समर्थक हैं, तो दूसरी ओर जो लोग हैं, उनमें विपक्षी दल हैं, कई पर्यावरणविद, इतिहासकार और लेखक हैं। यह विवाद अभी आगे चलता रहेगा और आखिरकार देखने की असली बात यही होगी कि जनमानस में इस भव्य और महत्वाकांक्षी परियोजना की क्या छवि बनती है।

# उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो ऋण

भरत झुनझुनवाला

वर्तमान कोरोना के संकट को पार करने के लिए भारत सरकार ने भारी मात्रा में ऋण लेने की नीति अपनाई है। ऋण के उपयोग दो प्रकार से होते हैं। यदि ऋण लेकर निवेश किया जाए तो उस निवेश से अतिरिक्त आय होती है और उस आय से ऋण का ब्याज एवं मूल का पुनर्भुगतान किया जा सकता है। जिस प्रकार उद्यमी ऋण लेकर उद्योग स्थापित करता है, अधिक लाभ कमाता है, और उस अतिरिक्त लाभ से ऋण का भुगतान करता है। ऐसे में ऋण का सदुपयोग उत्पादक कार्यों के लिए होता है। लेकिन यदि ऋण का उपयोग घाटे की भरपाई के लिए किया जाए तो उसका प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। खपत के लिए उपयोग किये गये ऋण से अतिरिक्त आय उत्पन्न नहीं होती बल्कि संकट के दौरान लिए गये ऋण पर अदा किए जाने वाले ब्याज का अतिरिक्त भार आ पड़ता है। जैसे किसी कर्मी की नौकरी छूट जाए और वह ऋण लेकर अपनी खपत को पूर्ववत बनाए रखे तो भी दुबारा नौकरी पर जाने के बाद लिए गये ऋण पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार उसकी शुद्ध आय में गिरावट आएगी। पूर्व में ब्याज नहीं देना पड़ता था जो कि अब देना पड़ेगा। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार समेत विश्व के तमाम विकासशील देशों द्वारा संकट पार करने के लिए ऋण लेने पर विचार करना होगा। ये ऋण नौकरी छूटने पर लिए गए ऋण के सामान है। चूंकि इनसे अतिरिक्त आय उत्पन्न नहीं हो रही है। इसलिए विश्व बैंक ने चेताया है कि ऋण लेकर संकट पार करने की नीति भविष्य में कष्टप्रद होगी। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण दिया है, जिसने भारी मात्रा में ऋण लिए। आज उस देश को खाद्य सामग्री प्राप्त करना भी दुश्वार हो गया है। चूंकि ब्याज का भारी बोझ आ पड़ा है। इसी क्रम में छह विकासशील देश जाम्बिया, एक्वाडोर, लेबनान, बेलीज, सूरीनाम और अर्जेंटीना ने अपने ऋण की अदायगी से वर्ष 2020 में ही डिफाल्ट कर दिया है। वे लिए गए ऋण का भुगतान नहीं कर सके हैं। साथ-साथ 90 विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से आपात ऋण की सुविधा की मांग की है। जिससे पता लगता है कि विकासशील देशों द्वारा लिये जाने वाले ऋण का प्रचलन फैल भी रहा है और उन्हें संकट में भी डाल भी रहा है। तुलना में अमेरिका और चीन द्वारा लिए गये ऋण का चरित्र कुछ भिन्न है। अमेरिकी सरकार ने भारी मात्रा में ऋण लेकर अपने नागरिकों को नगद ट्रांसफर किए हैं। लेकिन साथ-साथ उन्होंने नयी तकनीकों में भारी निवेश भी किया है। जैसे अमेरिकी सरकार ने बैक्टीरिया रोगों की रोकथाम के लिए प्रकृति में उपलब्ध फाज से उपचार के लिए सब्सिडी दी है। इसी प्रकार चीन ने अमेरिका और रूस के साथ अंतरिक्ष यान बनाने के स्थान पर स्वयं अपने बल पर अंतरिक्ष यान बनाना शुरू कर दिया है और उसका पहला हिस्सा अंतरिक्ष में भेज दिया है; चीन ने सूर्य के बराबर तापमान पैदा किया है; अपने ही लड़ाकू विमान बनाये हैं; और मंगल ग्रह पर अपने सेटेलाइट को उतारा है। ऐसे में अमेरिका और चीन द्वारा लिए गये ऋण का चरित्र भिन्न हो जाता है। ये उसी प्रकार हैं जैसे कि उद्यमी ऋण लेकर उद्योग स्थापित करता है और उससे अतरिक्त लाभ कमाता है। अतः भारत द्वारा ऋण लेकर संकट को पार करने की नीति उचित नहीं दिखती जबकि अमेरिका और चीन की ऋण लेकर निवेश करने की नीति सही दिशा में प्रतीत होती है। भारत सरकार द्वारा लिये जाना वाला ऋण एक और दृष्टि से संकट पैदा कर सकता है। पिछले महीने अप्रैल, 2021 में जीएसटी से प्राप्त राजस्व में भारी वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्ष में लगभग 1.0 लाख करोड़ रुपये प्रति माह से बढ़कर मार्च, 2021 में 1.23 लाख करोड़ और अप्रैल, 2021 में 1.41 लाख करोड़ का राजस्व जीएसटी से मिला है। इस आधार पर सरकार द्वारा लिया गया ऋण स्वीकार हो सकता है। लेकिन तमाम आंकड़े इतनी उत्साहवर्धक तस्वीर नहीं पेश करते । मैकेंजी द्वारा किए गये एक सर्वेक्षण में जनवरी, 2021 में देश के 86 प्रतिशत लोग देश की अर्थव्यवस्था के प्रति सकारात्मक थे जो कि अप्रैल, 2021 में घटकर 64 प्रतिशत हो गये थे। डिप्लोमेट पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अनुसार फैक्टरियों द्वारा बाजार से खरीद करने वाले मैनेजरों में मार्च 2021 में 54.6 प्रतिशत सकारात्मक थे जो अप्रैल में घटकर 54.0 प्रतिशत रह गये थे। मार्च और अप्रैल के बीच पेट्रोल की खपत में 6.3 प्रतिशत की गिरावट आई है, डीजल की खपत में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई है, कारों की बिक्री में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है और अन्तर्राज्यीय ईवे बिलों में 17 प्रतिशत की गिरावट आई है। अतः अर्थव्यवस्था के मूल आंकड़े मार्च की तुलना में अप्रैल में नकारात्मक हैं। इसके बावजूद जीएसटी की वसूली में भारी वृद्धि हुई है। इसका कारण संभवतः यह है कि बीती तिमाही में जो जीएसटी अदा किया जाना था वह अप्रैल में अदा किया गया है; अथवा सरकार ने जीएसटी के रिफंड रोक लिए हैं। और भी कारण हो सकते हैं जिनका गहन अन्वेषण करना जरूरी है। बहरहाल इतना स्पष्ट है कि जीएसटी की वसूली में वृद्धि के बावजूद मूल अर्थव्यवस्था की तस्वीर विपरीत दिशा में चल रही है। भारत सरकार ने दिसम्बर, 2019 में अपनी जीडीपी का 74 प्रतिशत ऋण ले रखा था जो दिसम्बर, 2020 में बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया है। इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने भारी मात्रा में ऋण लेने की घोषणा की थी जो कि कोविड की दूसरी और तीसरी लहर के कारण हुई क्षति के कारण और अधिक होगा। इस कठिन परिस्थिति में सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने चाहिये ताकि ऋण का बोझ न बढ़े। पहला यह कि ईंधन तेल के ऊपर आयात कर बढ़ाकर राजस्व वसूल करना चाहिए और इसकी खपत कम करनी चाहिए। दूसरा, सरकार को अपनी खपत में जैसे सरकारी कर्मियों के वेतन में समय की नाजुकता को देखते हुए भारी मात्रा में कटौती कर देनी चाहिए और अन्य अनुत्पादक खर्चों को समेटना चाहिए। तीसरा सरकार को नयी तकनीकों में भारी निवेश करना चाहिए। हमारे लिए यह शर्म की बात है कि दवाओं के क्षेत्र में अग्रणी होने के बावजूद आज हम अपने देश की भारत बायोटेक के टीके से आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं और तमाम देशों से टीके आयात कर रहे हैं। इसलिए इस कठिन परिस्थिति में अपने बल पर नयी तकनीकों में भारी निवेश करने की पहल करनी चाहिए अन्यथा यह ऋण देश की अर्थव्यवस्था को ले डूबेगा। जैसे वेनेजुएला जैसे देशों को यह संकट में डाल रहा है।

लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।

## 'आज के ट्वीट

### घंटी

**मंदिर में घंटियां होने के पीछे एक वैज्ञानिक सोच थी। जब आप घंटी बजाते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क के दाहिने और बाएँ भाग के बीच संतुलन बनाकर सुनने की सुध को सक्रिय करती हैं। यह ध्वनि 7 सेकंड तक टिकी रहती है। इससे उत्पन्न प्रतिध्वनि से शरीर में उपचार के सातों केंद्र खुल जाते हैं। - अर्णव गोस्वामी**

ज्ञान गंगा

## गौतम बुद्ध

आचार्य रजनीश ओशो/ गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है। और विशेषकर उनके लिए, जो सोच-विचार, चिंतन-मनन, विमर्श के आदी हैं। हृदय से भरे हुए लोग सुगमता से परमात्मा की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हृदय से भरे हुए लोग कहां हैं? और हृदय से भरने का कोई उपाय भी तो नहीं है। हो तो हो, न हो तो न हो। ऐसी आकस्मिक, नैसर्गिक बात पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। बुद्ध ने उनको चेताया जिनको चेताना सर्वाधिक कठिन है-विचार से भरे लोग, बुद्धिवादी, चिंतन-मननशील। प्रेम और भाव से भरे लोग तो परमात्मा की तरफ सरलता से झुक जाते हैं; उन्हें झुकाना नहीं पड़ता। उनसे कोई न भी कहे, तो भी वे पहुंच जाते हैं; उन्हें पहुंचाना नहीं पड़ता, लेकिन वे तो बहुत थोड़े हैं, और उनकी संख्या रोज थोड़ी होती गई है। उंगलियों पर गिने जा सकें, ऐसे लोग हैं। मुनष्य का विकास मस्तिष्क की तरफ हुआ है। मनुष्य मस्तिष्क से भरा है। इसलिए जहां जीसस हार जाएं, जहां कृष्ण की पकड़ न बैठे, वहां भी बुद्ध नहीं हारते हैं; वहां भी बुद्ध प्राणों के अंतरतम में पहुंच जाते हैं। बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म कहा गया है। बुद्धि पर उनका आदि तो है, अंत नहीं। शुरुआत बुद्धि से है। प्रारंभ बुद्धि से है। क्योंकि मनुष्य वहां खड़ा है, लेकिन अंत, अंत उसका बुद्धि में नहीं है। अंत तो परम अतिक्रमण है, जहां सब विचार खो जाते हैं, सब बुद्धिमत्ता विसर्जित हो जाती है; जहां केवल साक्षी, मात्र साक्षी शेष रह जाता है, लेकिन बुद्ध का प्रभाव उन लोगों में तत्क्षण अनुभव होता है जो सोच-विचार में कुशल हैं। बुद्ध के साथ मनुष्य-जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। पच्चीस सौ वर्ष पहले बुद्ध ने वह कहा जो आज भी सार्थक मालूम पड़ेगा, और जो आने वाली सदियों तक सार्थक रहेगा। बुद्ध ने विश्लेषण दिया, एनालिसिस दी। और जैसा सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने किया, कभी किसी ने न किया था, और फिर दुबारा कोई न कर पाया। उन्होंने जीवन की समस्या के उत्तर शास्त्र से नहीं दिए, विश्लेषण की प्रक्रिया से दिए। बुद्ध धर्म के पहले वैज्ञानिक हैं। उनके साथ श्रद्धा और आस्था की जरूरत नहीं है। उनके साथ तो समझ पर्याप्त है। अगर तुम समझने को राजी हो, तो तुम बुद्ध की नौका में सवार हो जाओगे। अगर श्रद्धा भी आएगी, तो समझ की छाया होगी, लेकिन समझ के पहले श्रद्धा की मांग बुद्ध की नहीं है। बुद्ध यह नहीं कहते कि जो मैं कहता हूं, भरोसा कर लो। बुद्ध कहते हैं, सोचो, विचारो, विश्लेषण करो; खोजो, पाओ अपने अनुभव से, तो भरोसा कर लेना।

# आज का राशिफल

**मेष** व्यावसायिक योजना सफल होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।

**वृषभ** बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। धन लाभ होगा।

**मिथुन** पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखकर वाद विवाद की स्थिति को टाला जा सकता है। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा।

**कर्क** आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। व्यावसायिक योजना सफल होगी। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य शिथिल होगा। विरोधी परास्त होंगे। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

**सिंह** प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अधीनस्थ कर्मचारी से तनाव मिलेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे।

**कन्या** दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। खान पान में संयम रखें। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

**तुला** आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। प्रणय संबंधों में कटुता आ सकती है। विरोधियों का पराभव होगा।

**वृश्चिक** आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। नेत्र विकार की संभावना है। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

**धनु** पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। भाई या पड़ोसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। धन लाभ की संभावना है।

**मकर** पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। स्थानान्तरण व परिवर्तन के योग हैं। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे।

**कुम्भ** शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।

**मीन** पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

# देश डेमोग्राफिक टाइम बम के निशाने पर

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

दुनिया के कुछ देश डेमोग्राफिक टाइम बम के निशाने में आ गए हैं। इस टाइम बम का कभी भी विस्फोट देखने को मिल सकता है। इसका असर अभी से जापान, चीन आदि देशों में दिखने लगा है। इसका एक बड़ा कारण इन देशों में काम-धंधा करने वाले युवाओं के अनुपात में बुजुर्गों की आबादी अधिक होना है। किसी भी देश में जीवन आयु बढ़ना एक अच्छा संकेत माना जा सकता है पर जिस तरह की इन देशों में जनसंख्या नियंत्रण की नीतियां चल रही है या चलाई गई थी उसका परिणाम यह है कि जनसंख्या नियंत्रण के कारण युवाओं की संख्या कम होती जा रही है। मेडिकल जर्नल लेंसेट में प्रकाशित अध्ययनों में इस बारे में चेताया जाता रहा है। इन हालातों को देखते हुए सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण नीति में बदलाव करने के कदम उठाए हैं। आज दुनिया के देशों में जापान सबसे बुजुर्ग देश बन गया है। यानी जापान में युवाओं की तुलना में बुजुर्ग आबादी बहुत अधिक हो गई है। जापान सरकार इस संकट से निपटने के लिए गंभीर होती जा रही है क्योंकि हालात यही रहे तो जापान में 2040 तक कुल आबादी की 35 प्रतिशत आबादी बुजुर्गों की हो जाएगी। दरअसल जापान में प्रजनन दर 1.4 के आसपास रह गई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार किसी भी देश की वर्तमान आबादी दर को बरकरार रखने के लिए प्रजनन दर 2.1 प्रतिशत होनी चाहिए। जापान में शतायु आयु के लोग भी दुनिया में सर्वाधिक हैं। अधिक आयु होना अच्छी बात है पर सबसे अधिक परेशानी का कारण यह हो जाता है कि काम करने वाले दो हाथों की संख्या पर बोझ अधिक हो जाता है। एक ओर बच्चों की आबादी तो दूसरी और बुजुर्गों की आबादी अनुत्पादक होने से अर्थव्यवस्था एवं परिवार व्यवस्था के संचालन पर सीधा असर पड़ता है। चीन की जनगणना की हालिया रिपोर्ट भी कम चिंतनीय नहीं है। चीन ने बढ़ती जनसंख्या के कारण 1979 में एक बच्चे की नीति अपनाई और इसका परिणाम यह रहा कि जनसंख्या पर तो नियंत्रण हो गया पर अब चीन के सामने दोहरा संकट उत्पन्न हो गया है। एक तो बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी और शादियों के लिए युवतियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर अकेले चीन में तीन करोड़ अविवाहित युवा हैं तो दूसरी ओर युवाओं में शादी के प्रति रुझान में भी कमी आ रही है। हालिया जनगणना रिपोर्ट के अनुसार चीन में 100 लड़कियों पर 111.3 लड़के हैं। साफ है कि लैंगिक अनुपात बुरी तरह से बिगड़ गया है। विशेषज्ञ प्रोफेसर ब्योर्न एल्परमैन का मानना है कि आज पैदा होने वाले बच्चे बड़े होकर विवाह योग्य होंगे तब उनमें से बहुत से लड़कों के सामने अपनी उम्र का जीवनसाथी की समस्या होगी। इसका एक बड़ा कारण भारत सहित दुनिया के अन्य देशों की तरह चीन में भी लड़कियों की तुलना में पुरुष शिशुओं को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। लाख समझाने व उपायों के बावजूद पुरुष शिशु पर अधिक जोर रहने से लड़कों की तुलना में लड़कियां कम हो रही हैं। इसके साथ ही चीन के युवाओं में भी शादी जैसे बंधन से युवाओं का मोहभंग होता जा रहा है। इस सबसे इतर ब्राजील एक अलग ही तरह की समस्या से जूझ रहा है। वहां किशोरावस्था में पहुंचते-पहुंचते गर्भधारण की समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए किशोरावस्था पहले, गर्भावस्था बाद में टेगलाइन से अभियान चला रही है। हालांकि आने वाले समय में ब्राजील भी डेमोग्राफिक बम की गिरफ्त में होगा। ईरान और इटली की समस्या भी कमतर नहीं है। इन देशों में जनसंख्या नियंत्रण हो चुका है और जन्म दर न्यूनतम स्तर पर आने से भविष्य में यहां की आबादी भी आज की आबादी की तुलना में कम हो जाएगी।

इटली में पलायन की समस्या भी एक बड़ा कारण है। यह कोई भारत की ही बात नहीं हैं अपितु दुनिया के अधिकांश देशों में देखा जा सकता है कि किसी भी योजना के संचालन से भविष्य में पड़ने वाले दुष्प्रभावों का आकलन समय पर नहीं किया जाता है और उसके दुष्परिणाम अधिक गंभीर हो जाते हैं। आज जापान बुजुर्गों का देश बन गया है। जल्दी ही चीन के हालात यही होने वाले हैं। भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं और इसका असर देखा जा रहा है। ईरान, इटली और ब्राजील की स्थिति भी सामने है। आज चीन एक ओर युवाओं को शादी करने को प्रेरित कर रही है तो दूसरी और युवाओं को दो बच्चे पैदा करने पर प्रोत्साहित करना भी शुरू कर दिया है। जापान में भी अपने स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। इटली में बच्चे पैदा करने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। ईरान के अपने प्रयास हैं। दरअसल जिस देश में अधिक युवाशक्ति होगी, काम करने वाले अधिक हाथ होंगे, वह देश आर्थिक दृष्टि से अधिक संपन्न होगा। हालांकि बढ़ती जनसंख्या इन देशों के सामने समस्या रही है पर चीन जैसे देश को चालीस साल में ही एक बच्चे की नीति को बदलने का निर्णय लेना पड़ा। इसी तरह से अन्य देश कर रहे हैं। डेमोग्राफिक टाइम बम की निशाने पर आने वाले देशों को अभी से अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी या यों कहे कि लोगों का दीर्घायु होना शुभ संकेत है तो यह जीवन स्तर में सुधार, पोषणयुक्त भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार सहित कई सुधारों के संकेत है और इसे अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन नई पीढ़ी में विवाह के प्रति विलगाव, जनसंख्या नियंत्रण पर बल और प्रजनन दर में कमी के कारण जो हालात बन रहे हैं वह गंभीर है। नहीं भूलना चाहिए कि विवाह और बच्चों के होने से विवाहितों में जिम्मेदारी का अहसास होता है तो समाज की व्यवस्था भी बनी रहती है। ऐसे में लैंगिक भेदभाव कम करने के साथ विवाह और परिवार संस्थाओं के प्रति युवाओं को जागरुक करना होगा। नहीं तो यह टाइम बम कभी विस्फोट कर गया तो इसके दुष्परिणाम और भी अधिक हानिकारक होंगे। भविष्य के लिए नीति बनाते समय उसके प्रभावों का भी आकलन करना होगा। यह किसी एक देश की समस्या नहीं है अपितु दुनिया के बहुत से देश इसकी जद में आने वाले हैं। ऐसे में ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो समाज और संसार दोनों के लिए हितकारक हो।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1



## कोविड-19 की दूसरी लहर से वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट, मारुति सुजुकी की बिक्री 71 फीसदी गिरी

**बिजनेस डेस्क:** कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण इस साल अप्रैल के मुकाबले मई में वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली। विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की घरेलू बिक्री घटकर 35,293 इकाई रह गई। इससे पहले अप्रैल में उसने 1,42,454 वाहन बेचे थे। निर्यात भी 17,237 इकाई से घटकर 11,262 इकाई रह गया। मारुति ने मई में 25,452 यात्री कार, 6,355 उपयोगी वाहन और 1,096 वैन बेचे। अप्रैल में उसकी यात्री कारों की बिक्री 98,926 इकाई, उपयोगी वाहनों की बिक्री 25,484 इकाई और वैनों की बिक्री 11,469 इकाई पर रही थी।

### टाटा मोटर्स की घरेलू बिक्री 38फीसदी घटी

टाटा मोटर्स ने मंगलवार को कहा कि मई में उसकी कुल घरेलू बिक्री अप्रैल की तुलना में 38 फीसदी घटकर 24,552 यूनिट की रह गई। अप्रैल में कंपनी ने 39,530 वाहन बेचे थे। कंपनी ने पिछले साल मई में 4,418 वाहनों की बिक्री की थी। टाटा मोटर्स ने कहा कि घरेलू बाजार में उसके यात्री वाहनों की बिक्री मई में 15,181 यूनिट की रही, जो इस साल अप्रैल की 25,095 यूनिट की बिक्री से 40 प्रतिशत कम है।

### महिन्द्रा एंड महिन्द्रा की बिक्री के आंकड़े

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस ने मई 2021 में 8004 यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की। अप्रैल 2021 के मुकाबले पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 56 फीसदी गिरी। कंपनी ने बयान में कहा कि पिछले साल मई में लॉकडाउन होने की वजह से मई 2020 और मई 2021 के बिक्री आंकड़ों की तुलना नहीं हो सकती है। महिन्द्रा के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बिक्री मई 2021 में 9443 यूनिट की रही।

### बजाज ऑटो की बिक्री बढ़ी

बजाज ऑटो ने मई 2021 में उसके कुल वाहनों की बिक्री पिछले साल के समान महीने की तुलना में 114 प्रतिशत बढ़कर 2,71,862 इकाई हो गई। बजाज ऑटो ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने पिछले साल मई में 1,27,128 वाहन बेचे थे। कंपनी ने कहा कि मई 2021 में घरेलू बिक्री 52 प्रतिशत बढ़कर 60,830 ईकाई हो गई, जो मई 2020 में 40,074 इकाई थी। समीक्षाधीन अवधि में कुल निर्यात 142 प्रतिशत बढ़कर 2,11,032 इकाई हो गया, जो मई 2020 में 87,054 इकाई था। एक अन्य विज्ञप्ति में एमजी मोटर इंडिया ने बताया कि मई 2021 में उनकी बिक्री 1,016 इकाई रही, जबकि पिछले साल के समान माह में यह आंकड़ा 710 था। कंपनी ने बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते उसका कारोबार प्रभावित हुआ।

### हुंदै की बिक्री घटी

हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने मंगलवार को कहा कि मई 2021 में उसकी कुल बिक्री 48 प्रतिशत घटकर 30,703 इकाई रह गई, जो अप्रैल 2021 में 59,203 इकाई थी। कंपनी ने बताया कि विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू प्रतिबंधों के कारण डीलरों को गाड़ियां भेजने में बाधा आई। एचएमआईएल ने बताया कि मई में घरेलू बिक्री 25,001 इकाई रही, जो अप्रैल में 49,002 इकाई थी। इस तरह घरेलू बिक्री में पूर्ववर्ती माह के मुकाबले 49 प्रतिशत की गिरावट हुई। कंपनी ने कहा कि पिछले महीने निर्यात 5,702 इकाई रहा, जो अप्रैल के 10,201 इकाई से 44 प्रतिशत कम है।

## डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों को पेटेंट छूट मामले में विधिवत प्रस्ताव रखकर बातचीत शुरू करनी चाहिए: भारत

**नयी दिल्ली,**

भारत ने कहा है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों को कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर पेटेंट छूट मामले में विधिवत प्रस्ताव के साथ बातचीत शुरू करने के लिये सहमति जताकर इस संकट के समय कुछ सुनिश्चितता लानी चाहिए। ट्रिप्स की 31 मई को अनौपचारिक बैठक में दिये अपने बयान में भारत ने कहा कि कुछ सदस्य देश अगर प्रक्रिया में देरी करने का प्रयास जारी रखते हैं, तो भी मूल विषय वस्तु आधारित बातचीत शुरू करने को लेकर तौर तरीके तलाशने का प्रयास जारी रहना चाहिये। इस संदर्भ में भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया समेत 62 सह-प्रायोजकों ने प्रस्ताव देकर कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा उत्पादों के विनिर्माण को लेकर पेटेंट से छूट की मांग की है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार अक्टूबर 2020 में कोविड-19 संक्रमण के इलाज और उसकी रोकथाम के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को ट्रिप्स (बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते) समझौते के कुछ प्रावधानों से छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखा था। ट्रिप्स समझौता जनवरी 1995 में लागू हुआ। यह कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, अघोषित सूचना या व्यापार संबंधी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर किया गया बहुपक्षीय समझौता है।भारत ने बयान में कहा, ''वायरस ने हमें छूट की आवश्यकता या लाभ के बारे में अनंतकाल तक चर्चा करने का समय नहीं दिया है।

हमें इस अनिश्चितता की घड़ी में छूट प्रस्ताव पर विधिवत दस्तावेज आधारित वार्ता शुरू करने के लिए सहमत होकर कुछ भरोसा कायम करना चाहिए।'' बयान के अनुसार अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे डब्ल्यूटीओ की साख को ज्यादा धक्का लगेगा और यह सामूहिक विफलता भावी पीढ़ी को याद रहेगी। इस प्रस्ताव पर पिछले कुछ महीनों में कई दौर की चर्चा हो चुकी है।

## कोल इंडिया की कोयला आपूर्ति मई में 38 प्रतिशत बढ़कर 5.5 करोड़ टन पर

**नयी दिल्ली.**

सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की कोयला आपूर्ति मई में 38 प्रतिशत बढ़कर 5.5 करोड़ टन पर पहुंच गयी। बिजली क्षेत्र की मांग में सुधार से कोल इंडिया की आपूर्ति बढ़ी है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा, ''बिजली क्षेत्र की कोयले की मांग सुधरने से कोल इंडिया ने किसी भी साल के मई माह के लिए अब तक सबसे अधिक 5.5 करोड़ टन का उठाव (आपूर्ति) का आंकड़ा दर्ज किया है। यदि कोविड-19 से पहले से तुलना की जाए, तो भी मई का उठाव का आंकड़ा 5.8 प्रतिशत बेहतर है। मई, 2019 में कोयले का उठाव 5.2 करोड़ टन रहा था। मई में बिजली क्षेत्र को कोल इंडिया की आपूर्ति 41 प्रतिशत बढ़कर 4.4 करोड़ टन पर पहुंच गई। पिछले साल मई की तुलना में कोल इंडिया ने बिजली क्षेत्र को 1.3 करोड़ टन की अधिक आपूर्ति की है। चालू वित्त वर्ष के पहले दो माह अप्रैल-मई में कोल इंडिया की कुल कोयला आपूर्ति 10.92 करोड़ टन रही, जो इससे पिछले साल की समान अवधि के 7.9 करोड़ टन से 38 प्रतिशत अधिक है।

## टीवीएस मोटर की मई में बिक्री 30 प्रतिशत घटी

**नयी दिल्ली,**

दोपहिया वाहन विनिर्माता टीवीएस मोटर कंपनी की इस साल मई में कुल बिक्री अप्रैल की तुलना में 30 प्रतिशत घट गयी। कंपनी ने अप्रैल में 2,38,983 इकाइयां बेची थीं जबकि मई में यह संख्या कम होकर 1,66,889 हो गयी।कंपनी ने पिछले साल मई में 58,906 इकाइयां बेची थी जब कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लगने से बिक्री पर असर पड़ा था। टीवीएस मोटर कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने मई 2021 में कुल 1,54,416 दोपहिया वाहन बेचे, यह संख्या अप्रैल में 2,26,193 थी। कंपनी ने मई 2020 में 56,218 दोपहिया वाहन बेचे थे। कंपनी ने मई 2021 में 1,25,188 मोटरसाइकिलें बेचीं जो अप्रैल में 1,33,227 थीं। मई 2020 में टीवीएस ने 26,772 मोटरसाइकिलें बेची थीं। टीवीएस ने मई 2021 में 19,627 स्कूटर बेचे, अप्रैल में यह संख्या 65,213 थी। कंपनी ने मई 2020 में 16,120 स्कूटर बेचे थे। पिछले महीने कंपनी की तिपहिया बिक्री 12,473 इकाई रही, जो अप्रैल में 12,790 इकाई और पिछले साल मई में 2,688 इकाई रही थी। कंपनी ने कहा, ÷कई राज्यों में लॉकडाउन की वजह से घरेलू बिक्री कम हुई लेकिन खुदरा बिक्री आपूर्ति से ज्यादा बनी रही। हमें उम्मीद है कि बाजार के दोबारा खुलने के साथ फिर से मांग बढ़ेगी।÷

## गौतम अडानी की इस कंपनी का शेयर नए रिकॉर्ड पर, निवेशकों की हुई चांदी

**बिजनेस डेस्क:**

गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर आज नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। मंगलवार को बीएसई पर कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर 8.5 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कंपीने के स्टॉक ने 1429.85 रुपए पर पहुंचकर अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। कारोबार की समाप्ति पर यह 7.56 फीसदी की तेजी के साथ 1415.25 पर बंद हुआ। इससे स्टॉक में निवेश करने वाले इंवेस्टर्स को काफी फायदा हुआ।

बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक इस तेजी के साथ ही अडानी एंटरप्राइजेज का मार्केट कैप 155650.62 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस शेयर का पिछला रिकॉर्ड 1350.5 रुपए का था जो उसने 19 मई 2021 को बनाया था। मई के महीने में इस शेयर में 13.6 फीसदी की तेजी आई जबकि इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 6.5 फीसदी बढ़ा। मार्च तिमाही में शानदार तिमाही के दम पर कंपनी के शेयरों में तेजी आई है।

**6.5 गुना बढ़ा मार्केट कैप**

वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेज का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 282.2 फीसदी बढ़कर 233.95 करोड़ रुपए रहा जो एक साल पहले समान तिमाही में 61.21 करोड़ रुपए रहा था। इस दौरान कंपनी की कंसोलिडेटेड इनकम 13,688.95 करोड़ रुपए रही जो पिछले साल समान तिमाही में 13,698.09 करोड़ रुपए रही थी। इस साल गौतम अडानी की नेटवर्थ में तेजी से इजाफा हुआ है। अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 8.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है जिनमें अडानी ग्रीन 1.99 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ टॉप पर है। मार्च 2020 में कोरोना काल के बाद शेयर बाजारों में आई तेजी का सबसे ज्यादा फायदा अडानी ग्रुप की कंपनियों को ही मिला है। इस साल अडानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब दोगुना हो चुका है। मार्च 2020 के बाद से इसमें 6.5 गुना उछाल आया है।

## मुनाफावसूली से शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद

### कच्चे तेल के दाम चढ़ने से ओएनजीसी में उछाल

**नयी दिल्ली,**

देश के शेयर बाजारों में मंगलवार को कारोबार सीमित दायरे में रहा और बीएसई सेंसेक्स तथा एनएसई निफ्टी दोनों में मामूली गिरावट रही। इसके साथ निफ्टी में पिछले सात कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर विराम लग गया। वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के बावजूद निवेशकों की मुनाफावसूली से बाजार में गिरावट रही। विश्लेषकों के अनुसार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट और वृहद आर्थिक आंकड़े संतोषजनक नहीं रहने से निवेशक बाजार से दूर रहे।

तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स में मंगलवार को पिछले चार कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर विराम लगा और यह कारोबार की समाप्ति पर 2.56 अंक की मामूली गिरावट के साथ 51,934.88 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 7.95 अंक यानी 0.05 प्रतिशत की हल्की गिरावट के साथ 15,574.85 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में आईसीआईसीआई बैंक रहा। इसमें 1.80 प्रतिशत की गिरावट रही। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, आईटीसी, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और इन्फोसिस भी नुकसान में रहे। दूसरी तरफ, ओएनजीसी में सर्वाधिक 3.52 प्रतिशत की तेजी रही। कच्चे तेल का दाम 70 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने के साथ कंपनी का शेयर चढ़ा है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज ऑटो और एचडीएफसी के शेयर भी लाभ में रहे। इनमें 2.93 प्रतिशत तक की तेजी आयी। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख विनोद मोदी ने कहा, ''सकारात्मक वैश्विक रुख के बावजूद मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी स्थिर बंद हुए। दवा कंपनियों को छोड़कर ज्यादातर प्रमुख खंडवार सूचकांक नुकसान में रहे।''उन्होंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर निवेशकों में आकर्षण बना हुआ है और इससे सूचकांक में कोई बड़ी गिरावट नहीं आयी। मझोले और छोटी कंपनियों के शेयरों में पिछले एक-दो दिन की तेजी के बाद मुनाफावसूली की गयी।एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख एस रंगनाथन ने कहा, ''शेयर बाजार सीमित दायरे में रहे और स्थिर बंद हुए....पीएमआई (परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स) आंकड़े संतोषजनक नहीं रहने से धारणा पर असर पड़ा... ।''

उन्होंने कहा, ''बाजार में हमने कुछ कपड़ा और दवा कंपनियों में निवेशकों की रूचि देखी।'' कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और मांग पर इसके हानिकारक प्रभाव से मई 2021 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में गिरावट देखने को मिली। आईएचएस मार्किट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) मई में गिरकर 50.8 पर आ गया, जो अप्रैल में 55.5 पर था। इस दौरान कंपनियों के पास नया काम और उत्पादन पिछले 10 महीनों में सबसे कम था। देश की अर्थव्यवस्था में मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में 7.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, यह गिरावट पूर्व में जताये गये विभिन्न अनुमानों से काफी कम है। इसका कारण कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से ठीक पहले चौथी तिमाही में वृद्धि दर का कुछ बेहतर रहना है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2020-21 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 1.6 प्रतिशत रही। यह इससे पिछली तिमाही अक्टूबर-दिसंबर, 2020 में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। तेल के दाम में तेजी के बावजूद वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में तेजी रही। एशिया के अन्य बाजारो में शंघाई, हांगकांग और सोल लाभ में रहे जबकि तोक्यो में गिरावट दर्ज की गयी। यूरोप के अन्य प्रमुख बाजारों में शुरूआती कारोबार में तेजी का रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.01 प्रतिशत बढ़कर 70.72 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे टूटकर 72.90 पर बंद हुआ।

## क्रिप्टोकरेंसी को लेकर RBI का बड़ा बयान, निवेशकों ने ली राहत की सांस

**बिजनेस डेस्क:**

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्रिप्टोकरेंसी में पूंजी लगाने वाले भारतीय निवेशकों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक 6 अप्रैल 2018 को जारी किए उसके जिस सर्कुलर का हवाला देकर अपने ग्राहकों को डिजिटल करेंसी की खरीद-फरोख त से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट 4 मार्च 2020 को खरिज कर चुका है। दूसरे शब दों में समझें तो रिजर्व बैंक के इस स्पष्टीकरण के बाद भारत में क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-फरोख्त का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक समेत देश कई सरकारी व निजी बैंकों ने अपने ग्राहकों को ई-मेल भेजकर वर्चुअल करेंसी में डील करने से दूर रहने की हिदायत दी थी। आरबीआई ने बैंकों और दूसरी संस्थाओं को हिदायत दी है कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के दौरान केवाईसी नियमों, एंटी मनी लॉड्रिंग और दूसरे नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। बता दें कि बैंकों ने आरबीआई के पुराने सर्कुलर का हवाला देकर अपने ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की सर्विसेज देने से भी इनकार कर दिया था। देश के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीर-एक्स (WazirX) को मई 2021 के दौरान अपने बैंकिंग पार्टनर्स के साथ कस्टमर फंड्स को डिपॉजिट और विद्ड्रॉ करने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी में डील करने पर अकाउंट सस्पेंड करने की चेतावनी भी दी थी। आरबीआई और एचडीएफसी बैंक समेत कई बैंकों की ओर से ग्राहकों को बिटक्वाइन व डॉगक्वाइन (Bitcoin/Dogecoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-फरोख्त से दूर रहने की चेतावनी भरे ई-मेल भेजे गए थे। साथ ही आगाह किया है कि चेतावनी नहीं मानने पर उनके बैंक कार्ड्स रद्द किए जा सकते हैं। इस पर रिजर्व बैंक ने स्थिति साफ करते हुए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों को राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक इस चेतावनी के लिए उसके जिस सर्कुलर का हवाला दे रहे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में उसके पुराने आदेश की वैधता खत्म हो गई है।

## एमएंडएम की बिक्री मई में 52 प्रतिशत घटकर 17,447 इकाई रही

**नयी दिल्ली,**

प्रमुख वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन के चलते मई 2021 में उसकी कुल बिक्री इससे पिछले महीने की तुलना में 52 प्रतिशत घटकर 17,447 वाहनों की रह गई। एमएंडएम ने कहा कि इस साल मार्च में उसने डीलरों को 36,437 इकाइयां भेजी थीं। कंपनी ने बताया कि घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री मई में 56 प्रतिशत घटकर 8,004 इकाई रह गई, जो अप्रैल 2021 में 18,285 इकाई रही थी। इसी तरह मई में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 53 प्रतिशत घटकर 7,508 इकाई रह गई, जो अप्रैल में 16,147 इकाई थी। एमएंडएम ने कहा कि पिछले महीने उसका निर्यात 1,935 इकाई रहा, जो अप्रैल में 2,005 इकाई था। महिंद्रा एंड महिंद्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ऑटोमोटिव प्रभाग) विजय नाकरा ने कहा, ''हमें अपने पूरे उत्पाद पोर्टफोलियो के लिए एक मजबूत वृद्धि की उम्मीद है। प्रतीक्षा अवधि बढ़ने के बावजूद थार की बुकिंग तेज है। एक्सयूवी300 को जबरदस्त सफलता मिली है और इसकी मजबूत मांग जारी है।'' उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों के कमी और बाजारों के क्रमिक रूप से खुलने के बाद कंपनी को मजबूत मांग की उम्मीद है।




## इस साल 20 प्रतिशत बढ़ेगा झींगा निर्यात, फिर शीर्ष पर पहुंच सकता है भारत: रिपोर्ट

**मुंबई,**

झींगा मछली का निर्यात, वर्ष 2021 में 20 प्रतिशत बढ़कर लगभग 4.3 अरब डॉलर का होने की उम्मीद है। पिछले साल कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न बाधाओं के उपरांत मांग के पुन¬ बढ़ने और आपूर्ति श्रृंखलाओं के फिर से बहाल होने के कारण झींगा मछली का निर्याति बढ़ने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2020 में दूसरे स्थान पर खिसकने के बाद भारत झींगा निर्यात में वैश्विक स्तर पर फिर शीर्ष स्थान हासिल कर सकता है। क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक राहुल गुहा ने कहा, भारत का झींगा निर्यात कैलेंडर वर्ष 2020 में 23 प्रतिशत कम हुआ है, जो प्रमुख निर्यात बाजारों में मांग में कमी और अमेरिका से मछली बीज स्टॉक की आपूर्ति में व्यवधान के कारण हुआ है, जिसने घरेलू झींगा फसल चक्र को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि महामारी की दूसरी लहर ने कच्चे माल और स्टॉक की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, इसलिए यह पहली लहर की तरह नुकसानदेह नहीं होगा।उन्होंने कहा, इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि निर्यातक अपने परिचालन को अच्छी तरह से प्रबंधित करेंगे और इस साल औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। वर्ष 2020 में, लॉकडाउन और आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान के कारण निर्यात 2019 के 4.7 अरब डॉलर से घटकर 3.6 अरब डॉलर रह गया। इक्वाडोर ने 3.7 अरब डॉलर के निर्यात के साथ भारत को पीछे छोड़ दिया क्योंकि वहां लॉजिस्टिक की दिक्कते कम थी और उसने कच्चे झींगे के लिए चीन की भारी मांग को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वैश्विक झींगा बिक्री में भारत, इक्वाडोर और वियतनाम की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत की है। गुणवत्ता और रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने तथा अमेरिका से अधिक उपयुक्त, विशिष्ट रोगाणु-मुक्त झींगा मछली बीज स्टॉक को अपनाने के कारण, भारत पिछले एक दशक में एक झींगा निर्यातक के रूप में प्रमुखता से उभरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उत्पादकों को राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए जलीय कृषि क्षेत्रों तथा बिजली और पूंजी के लिए दी जाने वाली सब्सिडी से भी लाभ प्राप्त हुआ है।

## अक्टूबर, 2020 से मई, 2021 के दौरान चीनी उत्पादन 13 प्रतिशत बढ़कर 305.68 लाख टन

**नयी दिल्ली,**

सितंबर को समाप्त होने वाले चालू विपणन वर्ष के पहले आठ महीनों में भारत का चीनी उत्पादन 13 प्रतिशत बढ़कर 305.68 लाख टन हो गया। व्यापार आंकड़ों के अनुसार, इस वृद्धि का मुख्य कारण महाराष्ट्र में अधिक उत्पादन का होना है।चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से लेकर सितंबर तक का होता है। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने एक बयान में कहा, ''देशभर की चीनी मिलों ने एक अक्टूबर, 2020 से 31 मई, 2021 के बीच 305.68 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है।'' एक साल पहले इसी अवधि में चीनी का उत्पादन 270.05 लाख टन का हुआ था। इस साल 31 मई तक केवल सात चीनी मिलें मुख्य रूप से दो राज्यों उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में गन्ने की पेराई कर रही थीं।उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन 110.16 लाख टन रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 125.46 लाख टन था। महाराष्ट्र में पेराई सत्र समाप्त हो गया है। राज्य में चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के 61.69 लाख टन की तुलना में बढ़कर 106.28 लाख टन हो गया। कर्नाटक में चीनी का उत्पादन 33.80 लाख टन से



बढ़कर 41.67 लाख टन हो गया। बंदरगाह की जानकारी और बाजार की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी मिलों ने सरकार द्वारा निर्धारित 60 लाख टन कोटा के मुकाबले निर्यात के लिए लगभग 58 लाख टन चीनी का अनुबंध किया है। इस्मा ने कहा, ''यह भी अनुमान है कि जनवरी, 2021 से मई, 2021 के दौरान लगभग 44-45 लाख टन चीनी का देश से निर्यात किया गया है।'' इसके अलावा चीनी उद्योग ने पिछले सत्र 2019-20 के निर्यात कोटे के मुकाबले अक्टूबर-दिसंबर 2020 तिमाही में 4.48 लाख टन चीनी का निर्यात किया था। हाल ही में, सरकार ने मौजूदा वैश्विक बाजार परिदृश्य का हवाला देते हुए, विपणन वर्ष 2020-21 के लिए चीनी के निर्यात में अपनी सहायता को 6,000 रुपये से घटाकर 4,000 रुपये प्रति टन कर दिया था। इस्मा ने कहा कि चीनी मिलें अपनी नकदी की स्थिति को मजबूत करने के लिए मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत और बिना किसी सरकारी सब्सिडी के चीनी का निर्यात कर रही हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## सार समाचार

### राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन से बातचीत की

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष पीटर डटन से बातचीत की। वार्ता मुख्य रूप से कोरोना वायरस से निपटने में दोनों देशों द्वारा उठाए गए कदमों पर केंद्रित था। बातचीत के बाद सिंह ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दोनों देश मंत्री स्तर की 'टू प्लस टू' वार्ता को जल्द आयोजित करने के लिए आशान्वित हैं। सिंह ने ट्वीट किया, ''ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन से कोविड-19 महामारी के खिलाफ दोनों देशों द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर बात हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक भागदारी के आधार पर लोगों के बीच गर्मजोशी भरे संबंध हैं।'' उन्होंने कहा, ''यह उल्लेख करना जरूरी होगा कि ऑस्ट्रेलियाई सैन्य बलों ने कोविड-19 से निपटने में भारत का भरपूर सहयोग किया है।'' पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑर ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच डिजिटल शिखर वार्ता के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समग्र रणनीतिक भागीदारी की थी और साजो सामान की मदद के लिए एक दूसरे के सैन्य बेस तक पहुंच को ले कर समझौता किया था। सिंह ने कहा, ''भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी के क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दोनों देश जल्द से जल्द मंत्री स्तरीय 'टू प्लस टू प्लस' वार्ता के लिए आशान्वित हैं।

### कांग्रेस आलाकमान से सिद्धू की मुलाकात, कहा- पंजाब के सच की आवाज बुलंदी से बताई है

नयी दिल्ली। पंजाब की सियासत में जारी उठापटक के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस सक्रिय हो गई है। कांग्रेस ने पंजाब के मनमुटाव को साधने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने लगातार दूसरे दिन पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मुखर होकर अपनी सारी बातें कहीं। मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा कि वे जमीनी स्तर के लोगों की आवाज उठाने के लिए आए हैं। उनका एक अपना स्टैंड है। लोगों की शक्ति लोगों के पास रहनी चाहिए और हमने इसके लिए हमेशा सच कहा है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सिद्धू ने कहा कि जो कुछ भी हाईकमान ने पार्टी के हित में पूछा उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया है। पंजाब के लोगों की आवाज हाईकमान तक पहुंचाने आया हूं और मेरा पक्ष है कि पंजाब के लोगों की वित्तीय ताकत जो टैक्स के रूप में सरकार को जाती है वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाई कमान को बुलंद आवाज में बताई है। पंजाब को जीताना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है।

### अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में कांग्रेस ने की आरोपियों को सजा दिलाने के लिए न्यायिक जांच की मांग की

अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)। कांग्रेस ने अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से कम से कम 36 लोगों की मौत के मामले की उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश से जांच कराए जाने की मांग की है। कांग्रेस सचिव विवेक बंसल ने मंगलवार को कहा कि अलीगढ़ जहरीली शराब कांड की जांच उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए ताकि इस पूरे गिरोह में शामिल लोगों के नाम सामने आ सकें। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ जिला प्रशासन ने सोमवार दोपहर तक 71 शवों के पोस्टमार्टम कराए जाने की बात तो स्वीकार की लेकिन तकनीकी पेंच फंसा कर मौतों के असल आंकड़े को कम कर दिया। बंसल ने यह भी बताया कि अनेक गांवों से मिल रही खबरों से जाहिर हो रहा है कि जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में मारे गए लोगों के शवों का, पोस्टमार्टम कराए बगैर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कांग्रेस सचिव ने कहा कि सिर्फ उच्च स्तरीय न्यायिक जांच से ही प्रभावित परिवारों को राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि शराब माफिया की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अधिकारियों से शराब के अवैध कारोबार के बारे में कई बार शिकायत की, लेकिन यह कारोबार जारी रहा।

### आंध्र प्रदेश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सर्वाधिक नए मामले आए सामने

अमरावती। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान आंध्र प्रदेश में संक्रमण के सर्वाधिक नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में मार्च से लेकर सितम्बर 2020 के बीच कोविड-19 की पहली लहर के दौरान मामले पांच लाख के पार चले गए थे, लेकिन दूसरी लहर के दौरान अकेले मई 2021 में 5.71 लाख मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार, मई 2021 की शुरुआत में राज्य में संक्रमण के 11.21 लाख मामले थे, जो माह अंत तक 16,93,085 हो गए। 25 मई तक हर पांच दिन में एक लाख मामले सामने आए। हालांकि इनमें एक बार फिर कमी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में एक महीने में 5.46 लाख लोग संक्रमण मुक्त हुए और 2,877 लोगों की इससे मौत हुई। आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल एक से 31 अगस्त के बीच संक्रमण की पहली लहर के दौरान 2.84 लाख मामले सामने आए थे, जिनमें से 2.53 लाख लोग संक्रमण मुक्त हुए और 2,562 लोगों की इससे मौत हुई। तब नमूनों के संक्रमित आने की दर 16.89 प्रतिशत तक पहुंच गई थी लेकिन इस साल मई में यह दर 25.56 ( 16 मई को) प्रतिशत हो गई थी। आंकड़ों के अनुसार, पांच मई को एक दिन में सर्वाधिक 1.16नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई।

# योगी के कामकाज को भाजपा ने सराहा, कोविड प्रबंधन को बताया बेमिसाल

**लखनऊ। (एजेंसी)।**

उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन को लेकर योगी सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। विपक्ष का यह तक आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पूरी तरह फेल रही। दावा यह भी किया जा रहा है कि भाजपा के कई नेता योगी सरकार के कोरोना प्रबंधन से खुश नहीं हैं। यह भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण की तस्वीर उभरी उससे सरकार की छवि खराब हुई है। यही कारण है कि पार्टी प्रदेश में कई स्तर पर बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इन सबके बीच पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने महामारी के प्रबंधन की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बेमिसाल बताया है।

कोरोना प्रबंधन को लेकर योगी सरकार के नाकाम रहने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का काम बेमिसाल रहा है। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सबसे मुश्किल दौर में भी लोगों की मदद की है। उन्होंने दावा किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उत्तर प्रदेश के कोविड-19 प्रबंधन को सराहा है। सिंह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में परिवर्तन की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह कुछ लोगों की कपोल कल्पना है। गौरतलब है कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और उनके स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वासपात्र सेवानिवृत्त अधिकारी और मौजूदा विधान परिषद सदस्य ए.के. शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी. एल. संतोष के साथ लखनऊ के तीन दिवसीय दौरे पर आए राधा मोहन सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट के बाद मंगलवार को उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य तथा दिनेश शर्मा से मुलाकात की।

भाजपा उपाध्यक्ष ने कानून मंत्री बृजेश पाठक से भी मुलाकात की। पाठक ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान संगठन से जुड़े मुद्दों तथा वर्ष 2022 के प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में विचार विमर्श हुआ, हालांकि उन्होंने विस्तार से कुछ भी बताने से मना कर दिया। पाठक ने पिछले अप्रैल माह में स्वास्थ्य विभाग को एक गोपनीय पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी को संभालने में विभाग की नाकामी का जिक्र किया था। कानून मंत्री के इस पत्र से सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था क्योंकि वह लगातार यह दावा कर रही थी कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं।

# केन्द्र से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की अपील की है: अरविंद केजरीवाल

**नयी दिल्ली। (एजेंसी)।**

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केन्द्र से कोविड हालात के मद्देनजर 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की अपील की और पिछले प्रदर्शन के आधार पर छात्रों के मूल्यांकन का सुझाव दिया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, 12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चे और अभिभावक काफी चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि बिना वैक्सिनेशन, 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। पिछले प्रदर्शन के आधार पर उन्हें आकलन किया जाए। केजरीवाल ने बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले यह अपील की। सीबीएसई ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते 14 अप्रैल को 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं के इम्तिहान स्थगित करने की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी, उन पर हाल ही में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से विस्तृत सुझाव मांगे थे। सरकार ने परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहे उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वह तीन जून तक इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगी।

## अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस का सरकार पर निशाना

# विपक्ष और अर्थशास्त्रियों की सलाह मानने को कहा

**नयी दिल्ली। (एजेंसी)।**

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट होने पर मंगलवार को चिंता प्रकट करते हुए कहा कि यदि 2021-21 में ऐसी स्थिति से बचना है तो सरकार को अपनी गलतियां स्वीकार करते हुए विपक्ष एवं अर्थशास्त्रियों की सलाह सुननी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने अर्थव्यवस्था की लिहाज से 2021-21 को पिछले चार दशक का 'सबसे अंधकारमय' साल करार दिया और यह आरोप भी लगाया कि 'अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर' इस सरकार का ''मास्टरस्ट्रोक'' है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, '' प्रधानमंत्री का 'हॉल ऑफ शेम' है- न्यूनतम जीडीपी, अधिकतम बेरोजगारी।'' इसी विषय को लेकर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने आरोप लगाया, ''विकास दरः -7.3, बेरोजगारी दरः 12 प्रतिशत। दूसरी लहर- 1 करोड़ नौकरियां खत्म। 2020- 97 प्रतिशत लोगों की आय घटी। पेट्रोल- 100 रुपये , सरसों का तेल- 200 रुपये और रसोई गैस- 809 रुपये। अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर÷ यही मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक है।''

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, '' जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था, वही हुआ। पिछले वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।'' चिदंबरम ने कहा कि 2018-19 में जीडीपी 140,03,316 करोड़ थी। 2019-20 में यह 145,69,268 करोड़ रुपये थी और 2020-21 में यह घटकर 135,12,740 करोड़ रुपये हो गई। यह देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताता है। उन्होंने दावा किया, ''साल 2020-21 पिछले चार दशक में देश की अर्थव्यवस्था का सबसे अंधकारमय साल रहा है। चारों तिमाही के आंकड़े अर्थव्यवस्था की कहानी बयां करते हैं।'' चिदंबरम ने कहा, ''पिछले साल जब कोरोना महामारी की पहली लहर धीमी पड़ती नजर आई तो वित्त मंत्री और मुख्य आर्थिक सलाहकार अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की बातें करने लगे...हमने कहा था कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन पैकेज की मजबूत मदद चाहिए।'' उन्होंने कहा कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद एक लाख रुपये से नीचे चला गया है। चिदंबरम ने आरोप लगाया, ''निश्चित तौर पर कोरोना महामारी का अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से असर पड़ा है, लेकिन अकुशल और अक्षम आर्थिक प्रबंधन ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को और बिगाड़ दिया।''

उन्होंने कहा, '' कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इसमें पहली लहर की तुलना में संक्रमण और मौतों की संख्या की लिहाज से ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर 2020-21 की तरह साल 2021-22 को नहीं होने देना है तो सरकार को जागना चाहिए, अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, अपनी नीतियां बदलनी चाहिए तथा विपक्ष एवं अर्थशास्त्रियों की सलाह स्वीकार करनी चाहिए।'' एक सवाल के जवाब में पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि नोट की छपाई होनी चाहिए तो वह कर सकती है क्योंकि भारत के पास ऐसा करने का संप्रभु अधिकार है। गौरतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था में 2020-21 में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आयी है जो गिरावट के बारे में पहले के विभिन्न अनुमानों से कम है। इसका कारण कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से ठीक पहले चौथी तिमाही में वृद्धि दर का कुछ बेहतर रहना है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2020-21 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 1.6 प्रतिशत रही। यह इससे पिछली तिमाही अक्टूबर-दिसंबर, 2020 में 0.5 प्रतिशत से अधिक है। वित्त वर्ष 2019-20 की जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

# सक्रिय मामलों में लगातार आ रही गिरावट, 344 जिलों में संक्रमण दर पांच प्रतिशत से कम: सरकार

**नई दिल्ली। (एजेंसी)।**

कोरोना वायरस को लेकर सरकार की ओर से राहत भरी खबर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में 29 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जहां प्रतिदिन 5000 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 28 अप्रैल से 4 मई के बीच देश में 531 ऐसे ज़िले थे जहां प्रतिदिन 100 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे। ऐसे ज़िले अब 295 रह गए हैं। 3 मई को देश में 17.13प्र. थे अब वह सिर्फ 6.73प्र. रह गए हैं। सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। आज एक दिन में देश में 1.3 लाख सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की गई है।

लव अग्रवाल ने आगे कहा कि 16-22 फरवरी के बीच प्रतिदिन देश में 7.7 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे थे। अब हम लगभग 20 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। अब तक हम देश में कुल 34.67 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में पॉजिटिविटी रेट 6.62प्र. दर्ज की गई है। देश में 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। तीस राज्यों में पिछले सप्ताह से कोविड-19 के उपचाराधीन मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश के 344 जिलों में कोविड-19 के मामलों की संक्रमण दर पांच प्रतिशत से कम है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक लव अग्रवाल ने कहा कि अब तक देश में 21.6 करोड़ वैक्सीन डोज़ दी जा चुकी हैं। 45 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग में 15.48 करोड़ डोज़, हेल्थकेयर को 1.67 करोड़ डोज़ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.42 करोड़ डोज़, 18-44 आयु वर्ग को 2.03 करोड़ डोज़ दी जा चुकी हैं। आपको बता दें कि भारत में अकेले मई में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के 88.82 से अधिक मामले सामने आये जो देश में अब तक संक्रमित 2.8 करोड़ से अधिक लोगों का 31.67 फीसद है। इस तरह, यह इस महामारी के दौरान सबसे खराब महीना रहा। मई में इस बीमारी के चलते 1,17,247 लोगों की जान भी गयी जो अब तक इस संक्रमण से हुई 3,29,100 मौतों का 35.63 प्रतिशत है। सात मई को 24 घंटे में अब तक कोविड-19 के सर्वाधिक 4,14,188 मामले सामने आये और 19 मई को सबसे अधिक 4529 मरीजों ने अपनी जान गंवायी।

# अलीगढ़: मस्जिद के सामने से गाजे-बाजे के साथ बारात निकालने को लेकर दो समुदायों में तनाव

**अलीगढ़ (उर प्रदेश)। (एजेंसी)।**

अलीगढ़ जिले के टप्पल क्षेत्र स्थित नूरपुर गांव में मस्जिद के सामने से गाजे-बाजे के साथ बारात निकाले जाने को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न होने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि नूरपुर गांव में गत 26 मई को बहुसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की बारात गाजे-बाजे के साथ एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। इस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने मस्जिद के आगे गाने बजाने पर आपत्ति जाहिर की थी। इस मामले में बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने एक मुकदमा दर्ज कराया जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बारात पर पथराव किया और लाठी से हमला किया।

इस घटना में अनेक लोगों को चोट आई और उनकी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस मामले में वकील, कलुआ, मुस्तकीम, शरफू, अंसार, सोहेल, फारूक, अमजद, तौफीक, शाजोर, लेहरु तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान तथा दलित एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवाह समारोह का आयोजन करने वाले परिवार के सदस्यों ने सोमवार को एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि वह 26 मई की घटना से बहुत व्यथित हैं और उन्होंने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ होने का पर्चा चिपका दिया है। वे किसी और स्थान पर पलायन करना चाहते हैं क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उन्हें परेशान करते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्रीय भाजपा सांसद सतीश गौतम और विधायक अनूप प्रधान ने गांव का दौरा किया और आश्वासन दिया कि किसी को भी अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सांसद गौतम ने कहा,'' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में किसी भी व्यक्ति के पलायन का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस मामले में दोषी लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी जो मिसाल बनेगी।''

# रामदेव की टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली के अस्पतालों में रेजीडेंट डॉक्टर्स का 'काला दिवस' प्रदर्शन

**नई दिल्ली। (एजेंसी)।**

ऐलोपैथी के संबंध में योग गुरु रामदेव की टिप्पणी से आहत दिल्ली के कई अस्पतालों के रेजिडेंट चिकित्सकों ने मंगलवार को राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत प्रदर्शन शुरू किया। चिकित्सकों की मांग है कि या तो रामदेव बिना शर्त माफी मांगें या उनके खिलाफ महामारी रोग अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) ने प्रदर्शन का आह्वान 29 मई को किया था और इस बात पर जोर दिया था कि आंदोलन के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होने दी जाएंगी।

दिल्ली के रेजिडेंट चिकित्सकों ने काली पट्टियां और रिबन पहनकर प्रदर्शन किया। फोर्डा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''रामदेव की टिप्पणियों के विरोध में हमारा प्रदर्शन मंगलवार सुबह शुरू हुआ। वह तो ऐलोपैथी के बारे में बोलने तक की योग्यता नहीं रखते हैं। इससे चिकित्सकों का मनोबल प्रभावित हुआ है जो (कोविड-19) महामारी से हर दिन लड़ रहे हैं। हमारी मांग है कि वह सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगे, अन्यथा महामारी रोग अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।'' उन्होंने बताया कि एम्स, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज-अस्पताल, हिंदूराव अस्पताल, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, बी.आर. आंबेडकर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं तथा कुछ अन्य भी शामिल होने वाले हैं। फोर्डा के अधिकारी ने बताया, ''विरोध स्वरूप कई चिकित्सकों ने बांहों पर काली पट्टी बांधी है। अन्य शहरों के चिकित्सक भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं।''

कुछ चिकित्सकों ने विरोध संदेश लिखे प्लेकार्ड ले रखे थे जबकि अन्य ने ऐसी पीपीई किट पहन रखी थीं, जिनके पीछे 'काला दिवस प्रदर्शन' लिखा था। फोर्डा इंडिया ने एक बयान जारी करके शनिवार को कहा था कि रामदेव के बयानों के प्रति आपत्ति जताए जाने के बावजूद ''अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किए बिना कार्यस्थलों पर एक जून, 2021 को राष्ट्रव्यापी काला दिवस प्रदर्शन की घोषणा कर रहे हैं''। बयान में कहा गया है, ''हम मांग करते हैं कि वह सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगे या उनके खिलाफ महामारी रोग कानून, 1897 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।'' फोर्डा ने यह भी आरोप लगाया कि रामदेव की टिप्पणी ने लोगों में ''टीकों को लेकर हिचकिचाहट'' भी बढ़ाई है। एम्स आरडीए ने एक बयान में कहा कि रामदेव की ऐसी ''अपमानजक टिप्पणियां स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा भड़काएंगी और इससे जन स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह ठप हो जाएगी।''

रामदेव को वायरल हुई वीडियो क्लिप में दिए गए उस बयान को वापस लेने के लिए हाल में मजबूर होना पड़ा था जिसमें वह कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर सवाल उठाते और यह कहते सुने गए कि ''कोविड-19 के लिए एलोपैथिक दवाएं लेने से लाखों लोग की मौत हो गई।'' इस टिप्पणी का चिकित्सकों के संघ ने जोरदार विरोध किया, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उनसे ''बेहद दुर्भाग्यपूर्ण'' बयान वापस लेने के लिए कहा। एक दिन बाद, योग गुरु ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ''खुले पत्र'' में भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) से 25 प्रश्न पूछे। इसमें पूछा गया था कि क्या एलोपैथी ने उच्च रक्तचाप और टाइप -1 और टाइप-2 मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए स्थायी राहत प्रदान की है।

## खासी मांग है देश के साथ-साथ विदेशों में भी

# मेडीकल लैब टैक्नीशियन की

"मेडीकल लैब टैक्नीशियन, डाक्टरों के निर्देश पर काम करते हैं। उपकरणों के रख-रखाव और कई तरह के काम इनके जिम्मे होता है। लैबोरेटरी में नमूनों की जांच और विश्लेषण में काम आने वाला घोल भी लैब टैक्नीशियन ही बनाते हैं। इन्हें मेडीकल साइंस के साथ-साथ लैब सुरक्षा नियमों और जरूरतों के बारे में पूरा ज्ञान होता है। लैब टैक्नीशियन नमूनों की जांच का काम करते हैं, लेकिन वे इसके परिणामों के विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित नहीं होते।"

नमूनों के परिणामों का विश्लेषण पैथोलॉजिस्ट या लैब टैक्नोलॉजिस्ट ही कर सकता है। जांच के दौरान एम.एल.टी. कुछ सैम्पलों को आगे की जांच या फिर जरूरत के अनुसार उन्हें सुरक्षित भी रख लेता है। एम.एल.टी. का काम बहुत ही जिम्मेदारी और चुनौती भरा होता है। इसमें धैर्य और निपुणता की बड़ी आवश्यकता होती है। जमा किए गए डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता की भी जिम्मेदारी उसकी होती है।

मेडीकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट में सर्टीफिकेट डिप्लोमा, डिग्री एवं मास्टर्स के दौरान बेसिक फिजियोलॉजी, बेसिक बायोकैमिस्ट्री एंड ब्लड बैंकिंग, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, एनवायरनमैंट एंड बायोमैडीकल वेस्ट मैनेजमैंट, मैडीकल लैबोरेटरी टैक्नोलॉजी एवं अस्पताल प्रशिक्षण दिया जाता है।

सर्टीफिकेट इन मैडीकल लैब टैक्नोलॉजी (सी.एम.एल.टी.) छह महीने का कोर्स है जिसके लिए योग्यता है 10वीं पास। वहीं डिप्लोमा इन मैडीकल लैब



टैक्नोलॉजी के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। इस कोर्स की अवधि है एक वर्ष। 12वीं प्रमुख विषय के रूप में फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी (पी.सी.बी.) तथा फिजिक्स, कैमिस्ट्री या मैथ्स (पी.सी.एम.) के साथ पास होना अनिवार्य है।

बी.एससी. इन एम.एल.टी. के लिए 12वीं विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। जिसकी अवधि है 3 वर्ष। एम.एस.सी. इन मैडीकल लैबोरेटरी टैक्नोलॉजिस्ट (एम.एल.टी.) प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए अभ्यर्थी के पास पहले हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, इसके बाद 2 साल का एसोसिएट प्रोग्राम करना होता है। यह प्रोग्राम कम्युनिटी कालेज, टैक्नीकल, स्कूल, वोकेशनल स्कूल या विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाता है।

मैडीकल लैबोरेटरी तकनीशियनों को काम में निपुणता और जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है।

छात्र इस तरह क प्रशिक्षण लैबोरेटरी कार्यों के दौरान ही साथ ही साथ प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर प्रांतों में मैडीकल लैबोरेटरी तकनीशियनों के लिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ राज्यों में इन तकनीशियनों के पास काम करने के लिए प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

प्रमाण पत्र वाले तकनीशियनों के लिए इस क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं होती हैं। आप किसी भी मैडीकल लैबोरेटरी हॉस्पिटल, पैथोलॉजिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। ब्लड बैंक में इनकी खासी मांग रहती है। आप बतौर रिसर्चर व कंसल्टैंट के अलावा खुद का क्लीनिक खोल सकते हैं।



सामान्य तौर पर एक एम.एल.टी. का वेतन 10 हजार से शुरू होता है जबकि पैथोलॉजिस्ट को तीस हजार रुपए से चालीस हजार रुपए तक सैलरी मिल जाती है। साथ ही योग्यता और तजुर्बे के आधार पर उनके वेतन में इजाफा होता चला जाता है। देश के साथ-साथ विदेशों में भी इनकी खासी मांग है।

## आधे से ज्यादा लोग अपनी जॉब से रहते हैं नाखुश!

क्या आप जानते हैं कि आधे से ज्यादा लोग अपनी नौकरी से नाखुश रहते हैं और आधे से ज्यादा लोग इस बात को महसूस करते हैं कि वह जिस जॉब को कर रहे हैं, उसमें उनका कोई भविष्य नहीं है या उन्होंने अपनी जिंदगी में गलत करियर चुन लिया।

यह बात ब्रिटेन स्टडी में सामने आई है। स्टडी में कहा गया है कि ब्रिटेन में काम करने वाले लोग अपनी जॉब से परेशान हैं और वह मानते हैं कि वह अपने भविष्य को सही जगह नहीं ले गए। इसके साथ ही एक चौथाई लोग अपने आपको गरीब कर्मचारी मानते हैं। वह लोग ऐसा इसिलए समझते हैं, क्योंकि वह अपनी जॉब से खुश नहीं होते।

स्टडी के मुताबिक 7 में से 1 कर्मचारी ऐसा भी होता है, जो अपनी जॉब से परेशान होकर उसकी आदर नहीं करते और वह जॉब पर ध्यान नहीं देता। इसके साथ-साथ 49 फीसदी ब्रिटेन के कर्मचारी ऐसे भी हैं, जो जॉब करने के साथ साथ किसी और फिल्ड में भी अपना कैरियर तलाश करते हैं।

## प्रतिद्वंद्वी को अपना अच्छा दोस्त बनाएं



### जब दोस्त ईर्ष्या करने लगे

कई बार ऑफिस में प्रमोशन मिलने से आपकी बैस्ट फ्रैंड को भी आपसे ईर्ष्या हो जाती है। ऐसे में अपनी ही दोस्त के बिहेवियर में जलन का भाव देख कर किसी को भी टैंशन होना लाजिमी है, उसे बताएं कि बहुत सी चीजें वक्त के साथ ही संभव हो पाती हैं, कल उसे भी तो प्रमोशन मिल सकता है, बस मेहनत करते रहो। इस प्रकार दो दोस्तों के दिलों में पड़ने वाली दीवार को समय रहते मिटाया जा सकता है।

### शिकायत करने वालों से बचें

ऐसे दोस्तों की भी कमी नहीं जिसे हमेशा आपसे कोई न कोई शिकायत रहती हो। हर बार कमी गिनाने वाले लोग पॉजीटिव सोच वाले नहीं हो सकते। अतः जरूरी है कि उसकी अधिकांश शिकायतों को उसकी आदत जान कर नजरअंदाज करना आरंभ करें। जब भी वह आपसे शिकायत करने लगे तो बात का टॉपिक ही बदल दें, यदि फिर भी वह न समझे, तो उसे साफ.-साफ कह दें कि हर समय अपनी कमी सुनना अपको पसंद नहीं और वह भी अपने नैगेटिव थॉट्स छोड़ कर पॉजीटिव बातों की तरफ ध्यान दे।

### हमेशा सलाह देने वालों से बचें

कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने फ्रैंड्स को परेशान देख कर बिना उसकी परेशानी का सबब जाने ही उसे सलाह देने बैठ जाएंगे, बिना यह जाने कि उसे इसकी जरूरत है भी या नहीं। ऐसे दोस्तों को लगता है कि आप में किसी प्रकार का फैसला लेने की क्षमता नहीं है और आपकी भलाई हमेशा उन्हें ऐसा करने को प्रेरित करती रहती है।

अब भले ही आपको यह सब बुरा लगे, पर इतनी सी बात पर दोस्ती कोई नहीं तोड़ता। अब की बार जब वह आपको बिन मांगे सलाह देने लगे तो बड़े प्यार से उसे यह समझाएं कि आप उसकी सलाह एवं राय का आदर करती हैं पर आप भी दूसरों की तरह अपनी ही गलतियों से सीखना चाहती हैं। यदि आपको उसकी सलाह की आवश्यकता होगी तो आप स्वयं उससे सलाह मांग लेंगी, तब तक उन्हें खुद ही इसका हल ढूंढने दिया जाए।

### खुद करें पहल

दोस्ती एक ऐसा फेवीकोल है जो बिखरते रिश्तों को मजबूती से जोड़ने का काम करता है। यदि आप किसी दूसरे से बेहतर बनना चाहती हैं, तो उसकी दोस्त बन जाएं, फिर आपको उससे प्रतिस्पर्धा करने में तनाव भी नहीं होगा और आपको एक नया दोस्त भी मिल जाएगा, जिससे आप प्रतिदिन कुछ नया सीखेंगी। नए रिश्ते बनाने में पहल किसी को तो करनी ही होती है, तो क्यों न आप ही शुरूआत करें क्योंकि प्रतिद्वंद्वी को ही अपना अच्छा दोस्त बनाने से बेहतर और क्या हो सकता है।

### बीती बातों को भुलाना बेहतर

कभी किसी दोस्त के लिए गुस्से में अपशब्द निकल गए हों तो उसे भुला कर उससे माफी मांग लें, क्योंकि बीती बातों को दोहराने का कोई लाभ नहीं। माफी मांग लेने से आप एक अच्छे दोस्त को खोने से बच जाएंगी और साथ ही उसकी नजरों में आपका स्थान और ऊंचा हो जाएगा।

# अनुवादक

## कॅरियर का बेहतरीन विकल्प

आज दुनिया भर के कई देशों में डिस्कवरी सबसे लोकप्रिय चैनल है। यह चैनल दुनिया के कई देशों में उनकी भाषा में प्रसारण करता है। ऐसा संभव होता है अनुवाद के कारण। अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जिसने ग्लोबल दुनिया को एक-दूसरे से जुड़ने में अहम भूमिका निभाई है। दुनिया की कई भाषाओं में अच्छे अनुवादकों की आज भारी मांग है। अच्छे अनुवादकों को अच्छा काम और अच्छा पैसा मिलने की चिंता नहीं करनी पड़ती है। अच्छे अनुवादक की योग्यताः यह ध्यान रखने की बात है कि अनुवाद मूल लेखन से भी मुश्किल है। सबसे पहले आपको अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा की जानकारी हो। इसके लिए महज फर्राटे से स्पैनिश और फ्रेंच बोलने से काम नहीं चल जाता। अनुवादक का मकसद एक से दूसरे भाषा क्षेत्र में जाना होता है। इसलिए इसके लिए धैर्य, स्थिरता और समय की जरूरत होती है। अनुवाद शुरू करने से लेकर खत्म करने तक में अनुवादक को कई तरह के प्रयोग करने होते हैं। शब्दों के विकल्पों में से सटीक शब्द चुनना होता है। मूल लेखन और टारगेट रीडर के बीच की दूरी खत्म करनी होती है। यह दूरी जितनी ज्यादा कम हो जाए, अनुवाद उतना सफल होता है। अवसरः शिक्षा और मीडिया से जुड़े लोगों के बीच अनुवाद के काम की बहुत मांग है। विभिन्न दूतावासों में भी अच्छे अनुवादकों की दरकार होती है। फिल्मों और धारावाहिकों में डबिंग के लिए भी अनुवादक की जरूरत होती है। एक प्रोफेशनल अनुवादक के लिए रोजगार के कई अवसर हैं। आज देश में लगभग पांच करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें तीन भाषाओं का ज्ञान है। आने वाले समय में यह संख्या बढ़ेगी जिसके कारण रोजगार की संख्या बढ़ेगी। जिन लोगों को दो या तीन भाषाओं की अच्छी जानकारी होती है, वे अनुवादक के रूप में अच्छा करिअर बना सकते हैं। अनुवाद का मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। अनुवाद दरअसल एक सेतु है, जो दो भाषाओं, दो संस्कृतियों और दो सभ्यताओं को आपस में जोड़ता है। भूमंडलीकरण के इस दौर में अनुवादकों की माँग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अनुवाद करने वालों के लिए प्रकाशन गृह में हमेशा स्थान होता है। इसके अलावा फिल्मी दुनिया में भी विदेशी फिल्मों के सबटाइटल' बनाने और किसी अन्य भाषा में फिल्म की डबिंग करने के लिए अनुवादकों की आवश्यकता होती है। अखबार और पत्रिकाओं में भी अनुवाद का बहुत काम होता है, इसलिए प्रिंट मीडिया में भी अनुवादकों के लिए अवसर मौजूद होते हैं। निजी क्षेत्र के अलावा शासकीय क्षेत्र में भी अनुवादकों के लिए रोजगार के कई अवसर उपलब्ध होते हैं। शासकीय दूतावासों में अनुवादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूतावास में काम करने वाले अनुवादकों को विदेश जाने के अवसर एवं प्रतिष्ठापूर्ण ओहदा मिलता है। कई लोग अनुवाद को केवल हिंदी और अंग्रेजी के साथ जोड़कर ही देखते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, अनुवाद के संदर्भ में हिंदी और अंग्रेजी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, लेकिन अन्य भाषाओं में भी अनुवाद के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। यदि हम अपने देश के बारे में बात करें तो हिंदी के अलावा गुजराती, मराठी, कन्नड, तमिल जैसी भाषाओं में भी अनुवादकों के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध हैं। यदि अनुवादक के रूप में नौकरी न करना चाहें तो फ्रीलांस अनुवादक के रूप में काम किया जा सकता है। फ्रीलांस अनुवादकों के लिए भी अवसरों की कमी नहीं है। फ्रीलांस अनुवादकों के लिए इंटरनेट बहुत बड़ा अवसरदाता है। कई वेबसाइट अनुवादकों को अवसर मुहैया करवा रही है। इन साइटों पर अनुवादक अपना पंजीयन करवाते हैं।

> भाषा संप्रेषण का माध्यम है लेकिन यदि भाषा पर अधिकार हो तो करिअर बनाने की डगर बहुत आसान हो जाती है। वैसे तो आप किसी भी क्षेत्र में अपना करिअर बनाएँ, दो या दो से अधिक भाषाओं पर अच्छी पकड़ आपको हर क्षेत्र में खास तवज्जो दिलाएगी। दो भाषाओं पर अच्छा अधिकार अपने आप में एक विशेषता है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## सार समाचार

### नेपाल में प्रतिनिधि सभा भंग किए जाने के मामले में संविधान पीठ गठित की जाएगी

काठमांडू। नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने प्रतिनिधि सभा को भंग किये जाने के खिलाफ दायर की गयी याचिकाओं की सुनवाई के लिये न्यायाधीशों की वरिष्ठता के आधार पर संविधान पीठ गठित करने पर मंगलवार को सहमति जतायी। इस मामले में न्यायाधीशों के बीच मतभेद के चलते सुनवाई स्थगित की जा चुकी है।

द हिमालयन टाइम्स समाचार पत्र की खबर के अनुसार पांच सदस्यीय संविधान पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के कामकाज के नियम में संशोधन करेंगे। खबर में बताया गया है कि दोनों पक्षों के सहमत होने पर एक सप्ताह के अंदर नियम में संशोधन किये जाने की उम्मीद है। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्ण मान शाक्य ने मीडिया से कहा, यह संशोधन न्यायाधीशों की वरिष्ठता के आधार पर पीठ का गठन सुनिश्चित करेगा। खबर के अनुसार इस घटनाक्रम के बाद, मंगलवार को मामले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित होने के आसार हैं।

### चीन में फिर कोरोना संक्रमण, ग्वांगझू के कई इलाकों में लॉकडाउन

बीजिंग। चीन के दक्षिणी हिस्से में स्थित औद्योगिक शहर ग्वांगझू में कोरोना वायरस के 11 नए मामले आने के बाद दो इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ग्वांगडोंग प्रांत के लोगों के लिए चीन के दूसरे हिस्सों में यात्रा करने से पहले कोराना वायरस की जांच को जरूरी बनाया गया है और संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर ही यात्रा की अनुमति दी जा रही है।

ग्वांगझू में 1.5 करोड़ की आबादी है लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मंगलवार को घोषित लॉकडाउन से कितने लोग प्रभावित हुए हैं। हालिया दिनों में शहर में स्थानीय स्तर पर संक्रमण के 30 से ज्यादा मामले आए हैं जिससे देश में संक्रमण का यह 'हॉटस्पॉट' बन गया है। चीन का मानना है कि उसने स्थानीय स्तर पर संक्रमण पर काबू पा लिया है। नए मामले आने पर मास्क पहनने, संपर्क का पता लगाने, सघन जांच और लॉकडाउन के कदम उठाए जाते हैं।

### कोविड-19 सहायता: भारतीय-अमेरिकी एनजीओ ने भारत में दिव्यांगों के लिए जुटाए 1 लाख डॉलर

वाशिंगटन। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित दिव्यांगजनों के लिए एक भारतीय-अमेरिकी गैर सरकारी संगठन ने 1,00,000 डॉलर इकट्ठे किए हैं। लॉस एंजिलिस के 'वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपुल' (वीओएसएपी) ने सोमवार को बताया कि उसने भारत में दिव्यांग लोगों के लिए 1,00,000 डॉलर जुटाए हैं, जिससे उन्हें वैश्विक महामारी के दौरान राशन, पीपीई किट और अन्य सामान मुहैया कराया जाएगा। एनजीओ ने एक बयान में कहा कि दिव्यांगजन (बच्चे या वरिष्ठ नागरिक या वयस्क) इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, इनमें अधिक लोग मारे गए हैं,उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ है और वे जीवन के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि अभी तक 4500 से अधिक लोगों को किराने के पैकेट और पीपीई किट भारत में बांटे गए हैं और लक्ष्य 10 हजार दिव्यांगजनों की मदद करना है। विज्ञप्ति के अनुसार, भारत में उसके साझेदार बीपीए के साथ गुजरात के विभिन्न जिलों, कर्नाटक के बेलगावी और मध्य प्रदेश के नागदा में राहत कार्य किए जा रहे हैं। इसका विस्तार हैदराबाद और पुणे में भी किया जा रहा है और देश भर में वीओएसएपी के सदस्य अपने-अपने शहरों तथा समुदाय में अधिक से अधिक दिव्यांगजन की मदद कर रहे हैं। वीओएसएपी को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) में 'स्पेशल कॉप्सलेटिव' का दर्जा प्राप्त है। इसके साथ 10,700 से अधिक स्वयंसेवक जुड़े हैं।

### यूरोप जा रहे प्रवासियों में से 3 बच्चों के शव बह कर लीबिया के तट पर पहुंचे: संयुक्त राष्ट्र

काहिरा। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी ने सोमवार को कहा कि संभवतया यूरोप जा रहे प्रवासियों के भूमध्य सागर में डूबने से मारे गए लोगों में तीन बच्चे भी शामिल हैं, जिनके शव बह कर लीबिया के तटीय शहर जुवारा में पाए गए हैं। एजेंसी ने बताया कि शव पिछले सप्ताह पाए गए हैं। जुवारा शहर राजधानी त्रिपोली के सौ किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इनमें छह माह के बच्चे और तीन वर्ष के बच्चे के शव शामिल हैं। उसने कहा, '' सुरक्षा और बेहतर जिंदगी के तलाश में खतरनाक रास्तों से निकले बच्चे बेवजह ही जिंदगी से हाथ धो रहे हैं।''

गौरतलब है कि शरण की आस में लीबिया से यूरोप जाने के मामले हाल के सप्ताह में बढ़े हैं और तस्कर लोगों की लाचारी का खूब फायदा उठा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) ने कहा कि इस वर्ष अब तक9,650से अधिक आव्रजकों और शरणार्थियों को बीच में रोक कर लीबिया वापस भेजा गया है। इनमें 480 से अधिक बच्चे शामिल थे।

# पाकिस्तान में सेना और सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकेगा मीडिया? नए नियमों के ड्राफ्ट पर बरपा हंगामा

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने मीडिया को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे लेकर पड़ोसी मुल्क में हंगामा बरपा है। विपक्षी दलों पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने नए कानून के प्रस्ताव को मीडिया मार्शल लॉ करार देते हुए कहा है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक का नियम है। इमरान खान की सरकार पाकिस्तान मीडिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 लाना चाहती है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पीएमएल-एन की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा कि यह मीडिया पर नियंत्रण की कोशिश है। इसके जरिए सरकार मीडिया संस्थानों को अपना मुखपत्र बना लेना चाहती है या फिर उन्हें बंद होना पड़ेगा। आइए जानते हैं, क्या हैं नए नियमों पर मीडिया को लेकर प्रस्ताव...

पाकिस्तान सरकार ने इस नए कानून के तहत मीडिया से जुड़े पिछले कई कानूनों के विलय का प्रस्ताव रखा है। इस नए कानून के तहत प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक की नियमावली तय की जाएगी। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि नए कानून के तहत एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जो देश में सभी तरह के मीडिया की नियमावली तय करेगी। नए नियमों के तहत देश में अखबार और डिजिटल मीडिया के संचालन के लिए भी टीवी चैनलों की तरह ही लाइसेंस की जरूरत होगी। इस ड्राफ्ट में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब चैनलों, वीडियो लॉग्स आदि को लेकर भी नियमावली तय करने की बात कही गई है।

इस अथॉरिटी में कुल 11 सदस्य होंगे और एक चेयरपर्सन होगा। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हालांकि विवाद इन प्रावधानों को लेकर नहीं है बल्कि सेना और सरकार पर मीडिया के तंज कसने पर रोक को लेकर है। प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट में कहा गया है कि किसी भी मीडिया की ओर से सेना, संसद, सरकार और उसके मुखिया को लेकर तंज नहीं कसा जा सकता, जिसके चलते हिंसा की आशंका हो या फिर उनकी मानहानि होती हो। नए कानून में इस नियम को लेकर ही सबसे ज्यादा आपत्ति जताई जा रही है और इसे पाकिस्तान का मीडिया मार्शल लॉ कहा जा रहा है।

## डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वेरिएंट्स को दिए नाम, भारत में मिले वायरस का नाम होगा डेल्टा और कप्पा

जिनेवा। (एजेंसी)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के विभिन्न स्वरूपों की नामावली की नई व्यवस्था की घोषणा की है। इन स्वरूपों को अब तक उनके तकनीकी अक्षर-संख्या कोड के नाम से जाना जाता है या उन देशों के स्वरूप के रूप में जाना जाता है जहां वे सबसे पहले सामने आए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि एक निष्पक्ष एवं समझने योग्य संतुलन बनाने के लिए अब वायरस के सबसे ज्यादा 'चिंताजनक' स्वरूपों की पहचान यूनानी के अक्षरों के जरिए होगी। इस तरह का एक स्वरूप जो सबसे पहले ब्रिटेन में नजर आया था और जिसे अब तक क्र1.1.7 नाम से जाना जाता है उसे अब से ''अल्फा'' स्वरूप कहा जाएगा। वायरस का क्र1.351 स्वरूप जिसे दक्षिण अफ्रीकी स्वरूप के नाम से भी जाना जाता है उसे 'बीटा' स्वरूप के नाम से जाना जाएगा।

ब्राजील में पाया गया तीसरा स्वरूप 'गामा' नाम से पहचाना जाएगा तथा भारत में सबसे पहले सामने आया वायरस का स्वरूप 'डेल्टा' कहलाएगा। आगे आने वाले चिंताजनक स्वरूपों को इसी क्रम में नाम दिया जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यह नई व्यवस्था विशेषज्ञों के समूहों की देन है। उसने कहा कि हालांकि वैज्ञानिक नामावली प्रणाली को खत्म नहीं किया जाएगा और नई व्यवस्था, स्वरूपों के ''सरल, बोलने तथा याद रखने में आसान'' नाम देने के लिए है।

# ब्रिक्स बैठक में भारत और चीन होंगे आमने-सामने, जानिए किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

बीजिंग। (एजेंसी)।

ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन ने मंगलवार को कहा कि वह साझा चिंता के मुद्दों पर इस पांच सदस्यीय समूह के अन्य देशों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने, एक दूसरे के रुख में तालमेल करने तथा आम-सहमति बनाने को लेकर आशान्वित है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अपने विदेश मंत्री वांग यी की ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) के विदेश मंत्रियों की डिजिटल बैठक में भाग लेने की घोषणा करते हुए यहां मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि यह सम्मेलन कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबारने की दिशा में खास महत्व रखता है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को बैठक बुलाई है। वेनबिन ने कहा, '' कोविड-19 और इस सदी में देखे गये अन्य बड़े बदलावों के सामूहिक प्रभाव के बीच ब्रिक्स तंत्र का महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबारने में उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों के बीच सहयोग गहन करने के लिहाज से विशेष महत्व है।'' उन्होंने कहा, ''ब्रिक्स नेताओं के मार्गदर्शन में पांचों देशों के विदेश मंत्री आपसी विश्वास को बढ़ाने तथा राजनीतिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए नियमित बैठक करते हैं।''

बैठक से चीन की अपेक्षा के प्रश्न पर प्रवक्ता ने कहा, ''चीन बैठक में साझा चिंताओं के अत्यावश्यक मुद्दों पर ब्रिक्स के अन्य देशों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने, एक दूसरे के रुख में तालमेल बैठाने तथा आम-सहमति बनाने को लेकर आशान्वित है।'' उन्होंने कहा, ''हम मिलकर यह कड़ा संदेश देंगे कि ब्रिक्स देश एकजुटता तथा सहयोग के साथ सच्चे बहुपक्षवाद का समर्थन करते हैं, महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को उबारने एवं वैश्विक चुनौतियों से निपटने को प्रोत्साहित करते हैं।'' बैठक की अध्यक्षता जयशंकर करेंगे। इसमें वांग के अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव और दक्षिण अफ्रीका की अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा सहयोग मंत्री ग्रेस नालेडी मांडिसा पैंडर के भाग लेने की उम्मीद है। ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अलबर्टो फ्रेंको भी इस डिजिटल बैठक में शामिल हो सकते हैं।

# कनाडा के स्कूल कैंपस में मिले 215 बच्चों के शव पर पीएम जस्टिन ट्रूडो बोले- ये पहली ऐसी घटना नहीं

टोरंटो। (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नेकहा कि एक स्कूल परिसर में 200 से अधिक बच्चों के शव दफन पाए जाने की घटना इस तरह की इकलौती घटना नहीं है। इस स्कूल को कभी कनाडा का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय माना जाता था। इस घटना के सामने आने के बाद सामुदायिक नेताओं ने मांग की कि हर उस स्थान की जांच की जाए जहां कभी कोई आवासीय स्कूल रहा हो। इसी की पृष्ठभूमि में ट्रूडो ने यह टिप्पणी की। ब्रिटिश कोलंबिया के सैलिश बोलने वाले एक समूह फर्स्ट नेशन की प्रमुख रोसेन कैसमिर ने कहा कि जमीन के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने वाले रडार की मदद से 215 बच्चों के शव मिले। इनमें कुछ तीन वर्ष की उम्र के बच्चों के शव हैं। उन्होंने शुक्रवार को बताया कि और शव मिल सकते हैं क्योंकि स्कूल के मैदान पर और हिस्सों की तलाशी ली जानी है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी क्षति है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और कैमलूप्स इंडियन रेजीडेंशियल स्कूल के दस्तावेजों में कभी इसका जिक्र नहीं किया गया। ट्रूडो ने कहा, 'प्रधानमंत्री के तौर पर उस शर्मनाक नीति के कारण स्तब्ध हूं जिसमें देश के बच्चों को उनके समुदायों से चुरा लिया जाता है। दुख की बात तो यह है कि यह इस तरह की इकलौती घटना नहीं है।' उन्होंने कहा, 'हमें सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा। आवासीय विद्यालय हमारे देश में एक सच्चाई है-एक त्रासदी हैं। बच्चों को उनके परिवारों से ले लिया जाता है और या तो उन्हें लौटाया ही नहीं जाता या फिर बुरी हालत में लौटाया जाता है। गौरतलब है कि 19वीं सदी से 1970 के दशक तक फर्स्ट नेशन के 1,50,000 से अधिक बच्चों को कनाडाई समाज में अपनाने के कार्यक्रम के तौर पर सरकार के वित्त पोषण वाले ईसाई स्कूलों में पढ़ना होता था। उन्हें ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए विवश किया जाता और अपनी मातृ बोलने नहीं दी जाती थी। कई बच्चों को पीटा जाता था तथा उन्हें अपशब्द कहे जाते और ऐसा बताया जाता है कि उस दौरान 6,000 बच्चों की मौत हो गयी थी। ट्रूथ एंड रिकांसिलिएशन कमीशन ने पांच वर्ष पहले संस्थान में बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर विस्तृत रिपोर्ट दी थी। कनाडा सरकार ने 2008 में संसद में माफी मांगी थी और स्कूलों में बच्चों के शारीरिक तथा यौन शोषण की बात स्वीकार की थी। ट्रूडो ने कहा कि वह अपने मंत्रियों से बात करेंगे कि समुदाय तथा जीवित बचे लोगों को मदद देने के लिए उनकी सरकार क्या कर सकती है। विपक्ष के नेता जगमीत सिंह ने सोमवार को संसद में आपात बहस की मांग की। उन्होंने कहा, 'इसमें हैरानी की बात नहीं है। आवासीय विद्यालयों की यही वास्तविकता है।' कैमलूप्स स्कूल 1890 से 1969 तक संचालित हुआ था। इसके बाद संघीय सरकार ने कैथलिक चर्च से इसका संचालन अपने हाथों में ले लिया। यह स्कूल 1978 में बंद हो गया था।

# चीन पर भारी पड़ी उसकी निति, अब बुजुर्गों की बढ़ती आबादी से परेशान ड्रैगन

बीजिंग। (एजेंसी)।

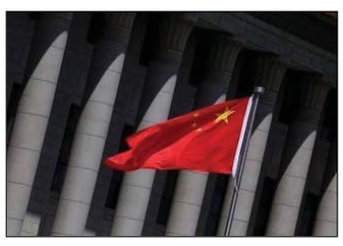

यू यान खुश हैं कि वह दो बेटियों की मां हैं लेकिन वह सोचती हैं कि आखिर चीन में कम महिलाएं ही क्यों बच्चे को जन्म दे पाती हैं जबकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार महिलाओं से बच्चे पैदा करने की अपील कर रही है। यू (35) की सुबह अपनी दो साल की बेटी की देखभाल में तो शाम का समय अपनी 10 साल की बेटी का गृहकार्य कराने में गुजरता है। यू ने यह सब करने के लिए रेस्टोरेंट की अपनी नौकरी छोड़ दी इसलिए परिवार अब उनकी पति की कमाई पर ही चलता है। यू ने कहा, ''अगर कोई युवा जोड़ा काम करने में व्यस्त है और उनके माता पिता बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते हैं तो वे बच्चे पैदा नहीं करना चाहेंगे।'' सत्तारूढ़ पार्टी ने सोमवार को प्रत्येक दंपति के लिए सिर्फ दो बच्चों की आधिकारिक नीति में बदलाव किया जिससे अब वे दो के बजाय तीन बच्चे रख सकते हैं।

चीन सरकार को इससे उम्मीद है कि वह चीनी समाज में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी से निपट पायेगी। लेकिन जन्म दर भी घट रही है। बढ़ती कीमत, रोजगार में बाधा और बुजुर्ग माता-पिता का ध्यान रखने की जिम्मेदारी के कारण युवा दंपति बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। वर्ष 1980 से लागू नीति के तहत अधिकतर दंपति एक संतान रख सकते थे लेकिन वर्ष 2015 में इसमें बदलाव कर दो संतान की इजाजत दी गयी। हालांकि इसके बावजूद चीन में बुजुर्गों की आबादी में इजाफा होता रहा। चीन की आबादी करीब 1.4 अरब है और इसमें इस दशक के आखिर में बढ़ोत्तरी की उम्मीद थी लेकिन अब उसमें गिरावट आनी शुरू हो गयी है। 11 मई को जारी जनगणना आंकड़े के अनुसार बुजुर्गों की आबादी में अनुमान से कहीं अधिक वृद्धि हो रही है।



इसमें यह भी कहा गया है कि धीमी आर्थिक वृद्धि को लेकर तैयारी और बुजुर्गों की मदद के लिए और अधिक काम करने की जरूरत है। बुजुर्गों की आबादी बढ़ने से चीन के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़त बनाने और खुशहाल उपभोक्ता प्रेरित अर्थव्यवस्था के रूप में खुद को स्थापित करने की उसकी मंशा बाधित हो सकती है। मेडिसन में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में वरिष्ठ प्रसूति एवं स्त्री रोग वैज्ञानिक यी फुक्सियान ने कहा, ''चीनी आबादी हमारी उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से बूढ़ी हो रही है।'' यी ने कहा, ''इससे आर्थिक विकास दर में गिरावट आयेगी।'' आधिकारिक शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने सोमवार को बैठक में सेवानिवृत्ति की आयुसीमा बढ़ाने पर जोर दिया।

## कोरोना के बाद चीन में आया बर्ड फ्लू के एच10एन3 स्ट्रेन से संक्रमित होने का पहला मामला

**बीजिंग।** मनुष्य के बर्ड फ्लू के एच10एन3 स्वरूप (स्ट्रेन) से संक्रमित होने का पहला मामला चीन के पूर्वी प्रात जियांग्सु में सामने आया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सरकारी सीजीएनटी टीवी ने बताया कि झेनजियांग शहर के 41 वर्षीय मरीज की हालत स्थिर है और उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने इस संक्रमण को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि यह मुर्गी से मनुष्यों में वायरस फैलने का छिटपुट मामला है और इससे महामारी फैलने का खतरा बहुत कम है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने एक बयान में बताया कि मरीज 28 मई को एच10एन3 वायरस से संक्रमित पाया गया था। आयोग ने यह नहीं बताया कि व्यक्ति संक्रमित कैसे हुआ। उसने बताया कि इससे पहले दुनिया में कहीं भी मनुष्यों में एच10एन3 संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। एच10एन3 मुर्गे-मुर्गियों में फैलने वाले में बर्डफ्लू का अपेक्षाकृत कम गंभीर स्वरूप है और इसके बड़े पैमाने पर फैलने का जोखिम बहुत कम है। चीन में बर्डफ्लू के विभिन्न स्वरूप हैं, जिनके मनुष्यों को संक्रमित करने के मामले भी कभी-कभी सामने आते हैं।

## बलूचिस्तान आतंकी हमले में चार पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के जवान की मौत, आठ घायल

इस्लामाबाद। बलूचिस्तान के अशांत दक्षिण-पश्चिमी प्रांत में पाकिस्तान की एक सुरक्षा चौकी पर आतंकवादियों ने हमला किया और इसके बाद आईईडी ले जा रहे सुरक्षा कर्मियों के वाहन को निशाना बनाया, जिसमें अर्धसैनिक बल के चार जवानों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हुए हैं।

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार, पहली घटना में आतंकवादियों ने क्वेटा में फ्रंटियर कोर (एफसी) के सैनिकों को निशाना बनाया। बयान के अनुसार, आतंकवादियों ने पीर इस्माइल जियारत के पास चौकी को निशाना बनाया। बयान के अनुसार, मुठभेड़ में '' चार-पांच आतंकवादी भी मारे गए, वहीं करीब आठ घायल हुए हैं।''इनके अलावा, ''चार सैनिक भी मारे गए जबकि छह घायल हो गए।''

वहीं, तुर्बत में एक अन्य घटना में आतंकवादियों ने फ्रंटियर कोर के एक वाहन को निशाना बनाया, जो आईईडी ले जा रहा था। इस घटना में दो सैनिक घायल हो गए। बयान में कहा गया, '' राज्य विरोधी ताकतों द्वारा, समर्थित विरोधी तत्वों द्वारा इस तरह की कायरतापूर्ण कार्रवाई की गई।''बयान में आगे कहा गया , लेकिन वे बलूचिस्तान में इतने परिश्रम के बाद अर्जित शांति और समृद्धि को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसने यह भी कि सुरक्षा बल उनके नापाक मंसूबों को नाकाम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। संसाधन संपन्न बलूचिस्तान में लंबे समय से तालिबान और बलूच राष्ट्रवादियों द्वारा कई बार हिंसक कृत्यों को अंजाम दिया जाता है। आईएसपीआर के एक बयान के अनुसार,आतंकवादियों ने इससे पहले नौ मई को भी क्वेटा और तुर्बत में सैनिकों पर दो हमले किए थे, जिसमें उनमें से तीन की मौत हो गई थी और पांच अन्य घायल हो गए थे।

# गलवान झड़प पर टिप्पणी करने वाला चीनी नागरिक हुआ गिरफ्तारी, जांच में जुटा चीन

बीजिंग। (एजेंसी)।

चीन ने सोमवार को कहा किवह उस मामले की जांच कर रहा है, जिसमें अमेरिका जा रहे 19 वर्षीय एक चीनी छात्र को दुबई में गिरफ्तार किया गया और बाद में उसे छोड़ दिया गया। पिछले साल गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद आधिकारिक मीडिया में आई खबरों को लेकर सवाल उठाने वाला यह लड़का पूछताछ के बाद यहां से भाग गया था। दुबई से प्राप्त मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक? अमेरिका के स्थायी निवासी वांग जिंगयू को तुर्की के इस्तांबुल जाते वक्त संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों द्वारा अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था।

रेडियो फ्री एशिया (आरएफए) ने 27 मई को खबर दी कि चीन से निकले लड़के को पारगमन के दौरान दुबई पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद 20 मई को उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मदद के लिये संदेश भेजा था। कार्यकर्ताओं और उसके समर्थकों ने कहा कि सादी वर्दी में पुलिस अधिकारियों ने वांग को तब गिरफ्तार किया जब वह न्यूयॉर्क की संपर्क उड़ान पकड़ने की कोशिश के तहत अमीरात की एक उड़ान से अप्रैल में दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरा था। आरएफए की खबर में कहा गया कि विदेश विभाग ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए इस मामले को ÷मानवाधिकार÷ चिंता का मामला बताया और चेतावनी दी कि उसे चीन में प्रत्यर्पण का सामना करना पड़ सकता है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से जब दुबई में वांग जिंग्यू की गिरफ्तारी और रिहाई पर टिप्पणी के लिये कहा गया तो, उन्होंने कहा ÷मैंने प्रासंगिक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है।÷ उन्होंने सोमवार को यहां मीडिया से कहा, ÷जब हम बोल रहे हैं, सक्षम चीनी प्राधिकारी इस मामले की जांच कानून के मुताबिक कर रहे हैं।÷ उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर किसी तरह की कयासबाजी नहीं होनी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात में आरएफए की मंदारिन सेवा से बात करते हुए वांग जिंग्यू ने कहा कि दुबई में विमान से उतरने के कुछ समय बाद ही उसे हिरासत में ले लिया गया। उसने कहा, ÷मैं पारगमन सुरक्षा जांच क्षेत्र की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी अचानक मुझे बिना किसी कारण के गेट पर रोका गया।÷ जिंग्यू ने आरएफए को बताया, ÷मुझ पर लगे आरोपों को हवा दी गई।÷ उसने कहा कि उसे हिरासत में लिये जाने के पीछे चीनी सरकार हो सकती है और आपराधिक मामले के बहाने उसे चीन लौटने को मजबूर किया जा सकता है।

भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के साथ पिछले साल 15 जून को हुई झड़प में 20 कर्मियों की शहादत की घोषणा की थी जबकि चीन की जन मुक्ति सेना ने करीब आठ महीने बाद खुलासा किया था कि उसके चार सैन्य कर्मी मारे गए थे जबकि एक अधिकारी घायल हुआ था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उद्धृत करते हुए असोसिएटेड प्रेस ने कहा कि वांग ने तब सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर सवाल किया था कि चीन सरकार ने चीनी सैनिकों की मौत के बारे में जानकारी देने के लिये छह महीने तक इंतजार क्यों किया। इसके बाद उसे प्रताड़ित करने का अभियान चलने लगा, जिसकी वजह से वह इस्तांबुल रवाना हो गया।

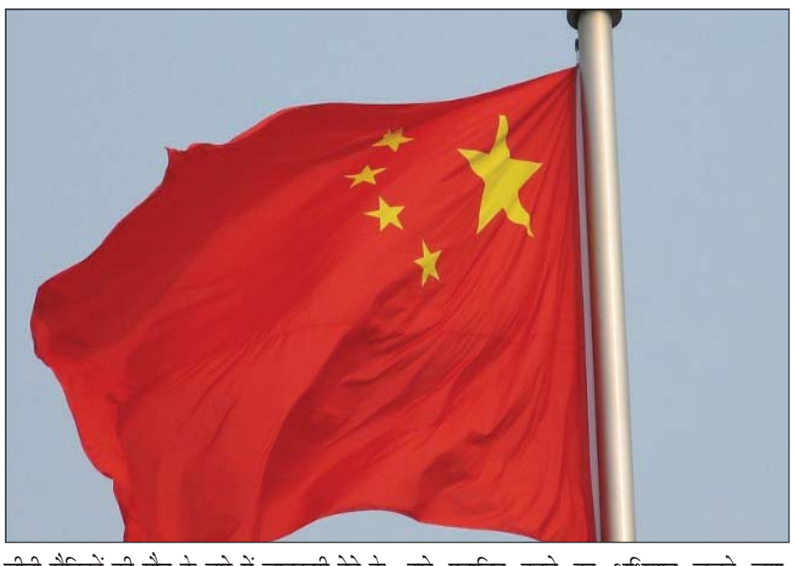

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

# फर्जी आरटी-पीसीआर रिपोट बनाने के गोरखधंधे का पर्दाफाश,एक शख्स गिरफ्तार

क्रांति समय दैनिक

वडोदरा,कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में लोगों की मजबूरी फायदा उठाने में धूर्त और लालची लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना महामारी के दौरान दवाईयां, इंजेक्शन और ऑक्सीजन इत्यादि कालाबाजारी के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब आरटी-पीसीआर टेस्ट पर फर्जी रिपोर्ट बनाने के गोरखधंधे का पर्दाफाश कर वडोदरा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वडोदरा क्राइम ब्रांच के मुताबिक वडोदरा के वारसिया क्षेत्र की हरिकृष्णा सोसायटी निवासी राकेश भगवानदास मीरचंदानी टूर्स एन्ड ट्रावेल्स का व्यवसाय करता है। कोरोना महामारी के दौरान राज्य से बाहर जाने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। इस मौके का फायदा उठाते हुए राकेश मीरचंदानी आरटी-पीसीआर की फर्जी रिपोर्ट बनाने लगा। पीडीएफ एडिटर नामक वेबसाइट का उपयोग कर पुरानी रिपोर्ट में छेड़छाड़ कर राकेश नई रिपोर्ट बना देता। पाथ और न्यूबर्क लेबोरेटरी के नाम से उन लोगों को फर्जी रिपोर्ट बना देता जो राज्य से बाहर जाना चाहते थे। फर्जी रिपोर्ट बनाने के लिए राकेश नेगेटिव के रु 300 और पॉजिटिव रिपोर्ट के लिए रु 800 वसूल करता। राज्य से बाहर जाने के लिए, कंपनियों में छुट्टी पाने और आर्थिक लाभ लेने के अलावा मेडिक्लेम इत्यादि मामलों में राकेश आरटी-पीसीआर की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर देता। राकेश वित्तीय लेन-देन ऑनलाइन करता था। आरटी-पीसीआर की फर्जी रिपोर्ट के बारे में सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच ने एक डमी ग्राहक भेजा था। वास्तविकता पता चलने के बाद क्राइम ब्रांच ने राकेश मीरचंदानी को गिरफ्तार कर लिया। जिसने पूछताछ में बताया कि पिछले 15 दिनों के भीतर उसने 50 से ज्यादा लोगों को फर्जी रिपोर्ट बनाकर दी है।

## शादी की चाह में अधेड़ ने गंवाएं लाखों रुपए, ठगे जाने का अहसास होने पर दर्ज करवाई

क्रांति समय दैनिक

दाहोद,शहर निवासी एक 59 वर्षीय व्यक्ति शादी की चाह में राजस्थानी ठग गिरोह का शिकार हो गया और रु 49 लाख से भी अधिक रकम गंवा दी। पीड़ित व्यक्तिकी शिकायत पर दाहोद पुलिस ने एक युवती समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरूकी है। जानकारी के मुताबिक दाहोद शहर के नवजीवन मिल रोड स्थित एक सोसायटी में रहने वाले मनोज बालकृष्ण सलूजा नामक 59 वर्षीय व्यक्ति ने शादी के लिए अखबार में विज्ञापन दिया था। जिसके आधार पर राजस्थान के अलवर जिले की किशनगढ़ तहसील के मनछाका गांव की अनिता चौधरी ने मनोज सलूजा से संपर्क किया और उससे शादी करने की तैयारी दर्शाई। व्यक्ति अनिता चौधरी की बातों में आ गया। जबकि अनिता

चौधरी, साहिर मोहम्मद नुरुद्दीन, तौफिक नुरुद्दीन और दिलीप यादव की ठग मंडली मनोज सलूजा को ठगने की साजिश बना चुके थे। राजस्थान की ठग मंडली ने 22 जुलाई 2016 से 18 दिसंबर 2019 के दौरान मनोज सलूजा से तीन अलग अलग बैंक एकाउंट में रु 48.59 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जिसके बाद मनोज सलूजा को राजस्थान के कोटा बुलाया। जहां दिलीप यादव उसे एक होटल में ले गया और अनिता को अपनी बहन बताते हुए व्यक्ति रु 50000 और ऐंठ लिए। साथ ही दिलीप यादव ने कहा कि वह जल्द ही अपनी बहन को लेकर दाहोद आएगा और दोनों परिवारों की उपस्थिति में शादी करवा देगा। करीब 49.09 लाख रुपए गंवा चुके मनोज सलूजा ऐसी आस लगाए बैठे रहे जो कभी पूरी नहीं होनेवाली थी। आखिरकार ठगे जाने का अहसास होने पर मनोज सलूजा ने दाहोद पुलिस थाने में अनिता चौधरी समेत चारों लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरूकी है।

## 'आप' के नगर पार्षदों की नई पहल, बैंच पर नहीं खर्च होगी अनुदान की रकम

क्रांति समय दैनिक

सूरत,सूरत महानगर पालिका में पहली बार बड़ी सफलता हासिल आम आदमी पार्टी (आप) के नगर पार्षदों नई पहल करते हुए ग्रांट में मिलने वाली रकम बैंच लगाने पर खर्च नहीं करने का फैसला किया है। ग्रांट की रकम का कहां और किस काम में उपयोग किया जाए, इसके लिए जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। आप के पार्षदों ने लोगों ग्रांट के उपयोग के बारे में लोगों का अभिप्राय जानने के लिए एक फार्म जारी किया है और इस फार्म में स्पष्ट कर दिया गया है कि ग्रांट में मिली रकम का बैंच लगाने में उपयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब नगर निगम में विपक्ष ने ग्रांट की रकम के उपयोग के बारे में लोगों से सुझाव मांगा हो। बता दें कि सूरत नगर निगम ने नगर पार्षदों को अनुदान की रकम आवंटित कर दी है। भाजपा के नगर पार्षदों के 93 नगर पार्षदों ने ग्रांट के तौर पर मिली रकम कोरोनाके लिए दे दी है। वहीं आप के नगर पार्षदों ने कोरोना के लिए एक भी रुपया नहीं दिया। आप के नगर पार्षदों का कहना है कि ग्रांट की रकम जनता की मर्जी से खर्च की जाएगी। जिसके लिए विपक्ष ने एक फार्म तैयार जारी किया है और उसके जरिए लोगों के अभिप्राय प्राप्त करेगा। जिसमें सोसायटी की आंतरिक सड़कें, गटर लाइन, पेयजल की लाइन, स्ट्रीट लाइट, पेवर ब्लोक फिटिंग, सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य के बारे में अभिप्राय प्राप्त किए जाएंगे। विपक्ष ने जारी फार्म में स्पष्ट कर दिया है कि वह ग्रांट की रकम से एक भी बेंच नहीं लगाएगा। सूरत नगर निगम में विपक्ष के नेता धर्मेश भंडारी ने बताया कि इससे पहले बैंच लगाने पर ग्रांट की सबसे ज्यादा रकम खर्च की जाती थी और लोगों के लिए जरूरी कामों पर बहुत कम उपयोग किया जाता था। इसलिए आप ने ग्रांट की रकम जनता के लिए खर्च करने का फैसला किया है। गौरतलब है मार्च महीने में हुए सूरत नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने 93 और आप ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जबकि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। कांग्रेस की हार से सूरत नगर निगम में आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में है।

## सार-समाचार

गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने नव नियुक्त अहमदाबाद शहर भाजपा प्रमुख अमित शाह को कमल का

फूल भेंट कर शुभकामनाएं दीं। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी और अहमदाबाद के पूर्व महापौर अमित शाह को शहर भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है।

### एम्ब्युलैंस और कार के बीच जबर्दस्त भिडंत, एक व्यक्तिकी मौत, 3 जखमी

भावनगर,भावनगर-तलाजा नेशनल हाईवे पर एम्ब्युलैंस और कार के बीच हुई टक्कर में एक शख्स की घटनास्थल पर मौत हो गई। जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को भावनगर के सर टी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक भावनगर निवासी एक शख्स अपनी मारुति ईको कार में अन्य तीन लोगों के साथ महुवा से भावनगर की ओर आ रहा था। उस वक्तभावनगर-तलाजा हाईवे पर मामसा जीआईडीसी के निकट भावनगर की ओर से आ रही एम्ब्युलैंस और कार के बीच जबर्दस्त भिडंत हो गई। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि दोनों वाहनों के आगे परखच्चे उड़ गए। कार में सवार चार में से एक शख्स को गंभीर चोट लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि अन्य तीन घायलों को भावनगर के सर टी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसमें एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई गई है। खबर मिलते ही वरतेज पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरूकर दी।

### भरुच एसओजी ने एक ही दिन में पकड़े 14 फर्जी डॉक्टर, बगैर कोई डिग्री कर रहे थे लोगों का इलाज

भरुच,भरुच एसओजी ने बगैर किसी मेडिकल डिग्री या सर्टिफिकेट के मेडिकल प्रेक्टिश कर रहे 14 फर्जी डॉक्टरों को दबोच कर कानूनी कार्रवाई शुरूकी है। कोरोना महामारी के बीच लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड कर रहे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ राज्यभर में पुलिस का खास अभियान चल रहा है। पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया के आदेश से जारी इस अभियान के तहत अब तक राज्य के कई जिलों से कई फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

क्रांति समय
Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## सार समाचार

### राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन से बातचीत की

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष पीटर डटन से बातचीत की। वार्ता मुख्य रूप से कोरोना वायरस से निपटने में दोनों देशों द्वारा उठाए गए कदमों पर केंद्रित था। बातचीत के बाद सिंह ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दोनों देश मंत्री स्तर की 'टू प्लस टू' वार्ता को जल्द आयोजित करने के लिए आशान्वित हैं। सिंह ने ट्वीट किया, ''ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन से कोविड-19 महामारी के खिलाफ दोनों देशों द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर बात हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक भागदारी के आधार पर लोगों के बीच गर्मजोशी भरे संबंध हैं।'' उन्होंने कहा, ''यह उल्लेख करना जरूरी होगा कि ऑस्ट्रेलियाई सैन्य बलों ने कोविड-19 से निपटने में भारत का भरपूर सहयोग किया है।'' पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑर ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच डिजिटल शिखर वार्ता के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समग्र रणनीतिक भागीदारी की थी और साजो सामान की मदद के लिए एक दूसरे के सैन्य बेस तक पहुंच को ले कर समझौता किया था। सिंह ने कहा, ''भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी के क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दोनों देश जल्द से जल्द मंत्री स्तरीय 'टू प्लस टू प्लस' वार्ता के लिए आशान्वित हैं।

### कांग्रेस आलाकमान से सिद्धू की मुलाकात, कहा- पंजाब के सच की आवाज बुलंदी से बताई है

नयी दिल्ली। पंजाब की सियासत में जारी उठापटक के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस सक्रिय हो गई है। कांग्रेस ने पंजाब के मनमुटाव को साधने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने लगातार दूसरे दिन पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मुखर होकर अपनी सारी बातें कहीं। मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा कि वे जमीनी स्तर के लोगों की आवाज उठाने के लिए आए हैं। उनका एक अपना स्टैंड है। लोगों की शक्ति लोगों के पास रहनी चाहिए और हमने इसके लिए हमेशा सच कहा है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सिद्धू ने कहा कि जो कुछ भी हाईकमान ने पार्टी के हित में पूछा उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया है। पंजाब के लोगों की आवाज हाईकमान तक पहुंचाने आया हूं और मेरा पक्ष है कि पंजाब के लोगों की वित्तीय ताकत जो टैक्स के रूप में सरकार को जाती है वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाई कमान को बुलंद आवाज में बताई है। पंजाब को जीताना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है।

### अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में कांग्रेस ने की आरोपियों को सजा दिलाने के लिए न्यायिक जांच की मांग की

अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)। कांग्रेस ने अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से कम से कम 36 लोगों की मौत के मामले की उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश से जांच कराए जाने की मांग की है। कांग्रेस सचिव विवेक बंसल ने मंगलवार को कहा कि अलीगढ़ जहरीली शराब कांड की जांच उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए ताकि इस पूरे गिरोह में शामिल लोगों के नाम सामने आ सकें। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ जिला प्रशासन ने सोमवार दोपहर तक 71 शवों के पोस्टमार्टम कराए जाने की बात तो स्वीकार की लेकिन तकनीकी पेंच फंसा कर मौतों के असल आंकड़े को कम कर दिया। बंसल ने यह भी बताया कि अनेक गांवों से मिल रही खबरों से जाहिर हो रहा है कि जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में मारे गए लोगों के शवों का, पोस्टमार्टम कराए बगैर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कांग्रेस सचिव ने कहा कि सिर्फ उच्च स्तरीय न्यायिक जांच से ही प्रभावित परिवारों को राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि शराब माफिया की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अधिकारियों से शराब के अवैध कारोबार के बारे में कई बार शिकायत की, लेकिन यह कारोबार जारी रहा।

### आंध्र प्रदेश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सर्वाधिक नए मामले आए सामने

अमरावती। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान आंध्र प्रदेश में संक्रमण के सर्वाधिक नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में मार्च से लेकर सितम्बर 2020 के बीच कोविड-19 की पहली लहर के दौरान मामले पांच लाख के पार चले गए थे, लेकिन दूसरी लहर के दौरान अकेले मई 2021 में 5.71 लाख मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार, मई 2021 की शुरुआत में राज्य में संक्रमण के 11.21 लाख मामले थे, जो माह अंत तक 16,93,085 हो गए। 25 मई तक हर पांच दिन में एक लाख मामले सामने आए। हालांकि इनमें एक बार फिर कमी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में एक महीने में 5.46 लाख लोग संक्रमण मुक्त हुए और 2,877 लोगों की इससे मौत हुई। आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल एक से 31 अगस्त के बीच संक्रमण की पहली लहर के दौरान 2.84 लाख मामले सामने आए थे, जिनमें से 2.53 लाख लोग संक्रमण मुक्त हुए और 2,562 लोगों की इससे मौत हुई। तब नमूनों के संक्रमित आने की दर 16.89 प्रतिशत तक पहुंच गई थी लेकिन इस साल मई में यह दर 25.56 (16 मई को) प्रतिशत हो गई थी। आंकड़ों के अनुसार, पांच मई को एक दिन में सर्वाधिक 1.16नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई।

# योगी के कामकाज को भाजपा ने सराहा, कोविड प्रबंधन को बताया बेमिसाल

**लखनऊ। (एजेंसी)।**

उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन को लेकर योगी सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। विपक्ष का यह तक आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पूरी तरह फेल रही। दावा यह भी किया जा रहा है कि भाजपा के कई नेता योगी सरकार के कोरोना प्रबंधन से खुश नहीं हैं। यह भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण की तस्वीर उभरी उससे सरकार की छवि खराब हुई है। यही कारण है कि पार्टी प्रदेश में कई स्तर पर बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इन सबके बीच पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने महामारी के प्रबंधन की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बेमिसाल बताया है।

कोरोना प्रबंधन को लेकर योगी सरकार के नाकाम रहने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का काम बेमिसाल रहा है। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सबसे मुश्किल दौर में भी लोगों की मदद की है। उन्होंने दावा किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उत्तर प्रदेश के कोविड-19 प्रबंधन को सराहा है। सिंह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में परिवर्तन की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह कुछ लोगों की कपोल कल्पना है। गौरतलब है कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और उनके स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वासपात्र सेवानिवृत्त अधिकारी और मौजूदा विधान परिषद सदस्य ए.के. शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी. एल. संतोष के साथ लखनऊ के तीन दिवसीय दौरे पर आए राधा मोहन सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट के बाद मंगलवार को उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य तथा दिनेश शर्मा से मुलाकात की।

भाजपा उपाध्यक्ष ने कानून मंत्री बृजेश पाठक से भी मुलाकात की। पाठक ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान संगठन से जुड़े मुद्दों तथा वर्ष 2022 के प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में विचार विमर्श हुआ, हालांकि उन्होंने विस्तार से कुछ भी बताने से मना कर दिया। पाठक ने पिछले अप्रैल माह में स्वास्थ्य विभाग को एक गोपनीय पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी को संभालने में विभाग की नाकामी का जिक्र किया था। कानून मंत्री के इस पत्र से सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था क्योंकि वह लगातार यह दावा कर रही थी कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं।

# केन्द्र से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की अपील की है: अरविंद केजरीवाल

**नयी दिल्ली। (एजेंसी)।**

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केन्द्र से कोविड हालात के मद्देनजर 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की अपील की और पिछले प्रदर्शन के आधार पर छात्रों के मूल्यांकन का सुझाव दिया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, 12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चे और अभिभावक काफी चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि बिना वैक्सिनेशन, 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। पिछले प्रदर्शन के आधार पर उन्हें आकलन किया जाए। केजरीवाल ने बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले यह अपील की। सीबीएसई ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते 14 अप्रैल को 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं के इम्तिहान स्थगित करने की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी, उन पर हाल ही में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से विस्तृत सुझाव मांगे थे। सरकार ने परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहे उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वह तीन जून तक इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगी।

## अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस का सरकार पर निशाना

# विपक्ष और अर्थशास्त्रियों की सलाह मानने को कहा

**नयी दिल्ली। (एजेंसी)।**

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट होने पर मंगलवार को चिंता प्रकट करते हुए कहा कि यदि 2021-21 में ऐसी स्थिति से बचना है तो सरकार को अपनी गलतियां स्वीकार करते हुए विपक्ष एवं अर्थशास्त्रियों की सलाह सुननी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने अर्थव्यवस्था की लिहाज से 2021-21 को पिछले चार दशक का 'सबसे अंधकारमय' साल करार दिया और यह आरोप भी लगाया कि 'अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर' इस सरकार का ''मास्टरस्ट्रोक'' है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ''प्रधानमंत्री का 'हॉल ऑफ शेम' है- न्यूनतम जीडीपी, अधिकतम बेरोजगारी।'' इसी विषय को लेकर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने आरोप लगाया, ''विकास दरः -7.3, बेरोजगारी दरः 12 प्रतिशत। दूसरी लहर- 1 करोड़ नौकरियां खत्म। 2020- 97 प्रतिशत लोगों की आय घटी। पेट्रोल- 100 रुपये , सरसों का तेल- 200 रुपये और रसोई गैस- 809 रुपये। अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर÷ यही मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक है।''

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, ''जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था, वही हुआ। पिछले वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।'' चिदंबरम ने कहा कि 2018-19 में जीडीपी 140,03,316 करोड़ थी। 2019-20 में यह 145,69,268 करोड़ रुपये थी और 2020-21 में यह घटकर 135,12,740 करोड़ रुपये हो गई। यह देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताता है। उन्होंने दावा किया, ''साल 2020-21 पिछले चार दशक में देश की अर्थव्यवस्था का सबसे अंधकारमय साल रहा है। चारों तिमाही के आंकड़े अर्थव्यवस्था की कहानी बयां करते हैं।'' चिदंबरम ने कहा, ''पिछले साल जब कोरोना महामारी की पहली लहर धीमी पड़ती नजर आई तो वित्त मंत्री और मुख्य आर्थिक सलाहकार अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की बातें करने लगे...हमने कहा था कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन पैकेज की मजबूत मदद चाहिए।'' उन्होंने कहा कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद एक लाख रुपये से नीचे चला गया है। चिदंबरम ने आरोप लगाया, ''निश्चित तौर पर कोरोना महामारी का अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से असर पड़ा है, लेकिन अकुशल और अक्षम आर्थिक प्रबंधन ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को और बिगाड़ दिया।''



उन्होंने कहा, '' कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इसमें पहली लहर की तुलना में संक्रमण और मौतों की संख्या की लिहाज से ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर 2020-21 की तरह साल 2021-22 को नहीं होने देना है तो सरकार को जागना चाहिए, अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, अपनी नीतियां बदलनी चाहिए तथा विपक्ष एवं अर्थशास्त्रियों की सलाह स्वीकार करनी चाहिए।'' एक सवाल के जवाब में पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि नोट की छपाई होनी चाहिए तो वह कर सकती है क्योंकि भारत के पास ऐसा करने का संप्रभु अधिकार है। गौरतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था में 2020-21 में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आयी है जो गिरावट के बारे में पहले के विभिन्न अनुमानों से कम है। इसका कारण कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से ठीक पहले चौथी तिमाही में वृद्धि दर का कुछ बेहतर रहना है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2020-21 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 1.6 प्रतिशत रही। यह इससे पिछली तिमाही अक्टूबर-दिसंबर, 2020 में 0.5 प्रतिशत से अधिक है। वित्त वर्ष 2019-20 की जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

# सक्रिय मामलों में लगातार आ रही गिरावट, 344 जिलों में संक्रमण दर पांच प्रतिशत से कम: सरकार

**नई दिल्ली। (एजेंसी)।**

कोरोना वायरस को लेकर सरकार की ओर से राहत भरी खबर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में 29 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जहां प्रतिदिन 5000 से कम मामले दर्ज़ किए जा रहे हैं। 28 अप्रैल से 4 मई के बीच देश में 531 ऐसे जलि थे जहां प्रतिदिन 100 से अधिक मामले दर्ज़ किए जा रहे थे। ऐसे जलि अब 295 रह गए हैं। 3 मई को देश में 17.13प्र. थे अब वह सिर्फ 6.73प्र. रह गए हैं। सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दर्ज़ की गई है। आज एक दिन में देश में 1.3 लाख सक्रिय मामलों में कमी दर्ज़ की गई है।

लव अग्रवाल ने आगे कहा कि 16-22 फरवरी के बीच प्रतिदिन देश में 7.7 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे थे। अब हम लगभग 20 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। अब तक हम देश में कुल 34.67 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में पॉजिटिविटी रेट 6.62प्र. दर्ज़ की गई है। देश में 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी दर्ज़ की जा रही है। तीस राज्यों में पिछले सप्ताह से कोविड-19 के उपचाराधीन मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश के 344 जिलों में कोविड-19 के मामलों की संक्रमण दर पांच प्रतिशत से कम है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक लव अग्रवाल ने कहा कि अब तक देश में 21.6 करोड़ वैक्सीन डोज़ दी जा चुकी हैं। 45 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग में 15.48 करोड़ डोज़, हेल्थकेयर को 1.67 करोड़ डोज़ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.42 करोड़ डोज़, 18-44 आयु वर्ग को 2.03 करोड़ डोज़ दी जा चुकी हैं। आपको बता दें कि भारत में अकेले मई में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के 88.82 से



अधिक मामले सामने आये जो देश में अब तक संक्रमित 2.8 करोड़ से अधिक लोगों का 31.67 फीसद है। इस तरह, यह इस महामारी के दौरान सबसे खराब महीना रहा। मई में इस बीमारी के चलते 1,17,247 लोगों की जान भी गयी जो अब तक इस संक्रमण से हुई 3,29,100 मौतों का 35.63 प्रतिशत है। सात मई को 24 घंटे में अब तक कोविड-19 के सर्वाधिक 4,14,188 मामले सामने आये और 19 मई को सबसे अधिक 4529 मरीजों ने अपनी जान गंवायी।

# अलीगढ़: मस्जिद के सामने से गाजे-बाजे के साथ बारात निकालने को लेकर दो समुदायों में तनाव

**अलीगढ़ (उर प्रदेश)। (एजेंसी)।**

अलीगढ़ जिले के टप्पल क्षेत्र स्थित नूरपुर गांव में मस्जिद के सामने से गाजे-बाजे के साथ बारात निकाले जाने को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न होने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि नूरपुर गांव में गत 26 मई को बहुसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की बारात गाजे-बाजे के साथ एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। इस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने मस्जिद के आगे गाने बजाने पर आपत्ति जाहिर की थी। इस मामले में बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने एक मुकदमा दर्ज कराया जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बारात पर पथराव किया और लाठी से हमला किया।

इस घटना में अनेक लोगों को चोट आई और उनकी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस मामले में वकील, कलुआ, मुस्तकीम, शरफू, अंसार, सोहेल, फारूक, अमजद, तौफीक, शाजोर, लेहरु तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान तथा दलित एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवाह समारोह का आयोजन करने वाले परिवार के सदस्यों ने सोमवार को एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि वह 26 मई की घटना से बहुत व्यथित हैं और उन्होंने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ होने का पर्चा चिपका दिया है। वे किसी और स्थान पर पलायन करना चाहते हैं क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उन्हें परेशान करते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्रीय भाजपा सांसद सतीश गौतम और विधायक अनूप प्रधान ने गांव का दौरा किया और आश्वासन दिया कि किसी को भी अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सांसद गौतम ने कहा,'' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में किसी भी व्यक्ति के पलायन का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस मामले में दोषी लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी जो मिसाल बनेगी।''

# रामदेव की टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली के अस्पतालों में रेजीडेंट डॉक्टर्स का 'काला दिवस' प्रदर्शन

**नई दिल्ली। (एजेंसी)।**

ऐलोपैथी के संबंध में योग गुरु रामदेव की टिप्पणी से आहत दिल्ली के कई अस्पतालों के रेजिडेंट चिकित्सकों ने मंगलवार को राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत प्रदर्शन शुरू किया। चिकित्सकों की मांग है कि या तो रामदेव बिना शर्त माफी मांगें या उनके खिलाफ महामारी रोग अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) ने प्रदर्शन का आह्वान 29 मई को किया था और इस बात पर जोर दिया था कि आंदोलन के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होने दी जाएंगी।




दिल्ली के रेजिडेंट चिकित्सकों ने काली पट्टियां और रिबन पहनकर प्रदर्शन किया। फोर्डा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''रामदेव की टिप्पणियों के विरोध में हमारा प्रदर्शन मंगलवार सुबह शुरू हुआ। वह तो ऐलोपैथी के बारे में बोलने तक की योग्यता नहीं रखते हैं। इससे चिकित्सकों का मनोबल प्रभावित हुआ है जो (कोविड-19) महामारी से हर दिन लड़ रहे हैं। हमारी मांग है कि वह सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगे, अन्यथा महामारी रोग अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।'' उन्होंने बताया कि एम्स, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज-अस्पताल, हिंदूराव अस्पताल, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, बी.आर. आंबेडकर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं तथा कुछ अन्य भी शामिल होने वाले हैं। फोर्डा के अधिकारी ने बताया, ''विरोध स्वरूप कई चिकित्सकों ने बांहों पर काली पट्टी बांधी है। अन्य शहरों के चिकित्सक भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं।''

कुछ चिकित्सकों ने विरोध संदेश लिखे प्लेकार्ड ले रखे थे जबकि अन्य ने ऐसी पीपीई किट पहन रखी थीं, जिनके पीछे 'काला दिवस प्रदर्शन' लिखा था। फोर्डा इंडिया ने एक बयान जारी करके शनिवार को कहा था कि रामदेव के बयानों के प्रति आपत्ति जताए जाने के बावजूद ''अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किए बिना कार्यस्थलों पर एक जून, 2021 को राष्ट्रव्यापी काला दिवस प्रदर्शन की घोषणा कर रहे हैं''। बयान में कहा गया है, ''हम मांग करते हैं कि वह सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगे या उनके खिलाफ महामारी रोग कानून, 1897 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।'' फोर्डा ने यह भी आरोप लगाया कि रामदेव की टिप्पणी ने लोगों में ''टीकों को लेकर हिचकिचाहट'' भी बढ़ाई है। एम्स आरडीए ने एक बयान में कहा कि रामदेव की ऐसी ''अपमानजक टिप्पणियां स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा भड़काएंगी और इससे जन स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह ठप हो जाएगी।''

रामदेव को वायरल हुई वीडियो क्लिप में दिए गए उस बयान को वापस लेने के लिए हाल में मजबूर होना पड़ा था जिसमें वह कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर सवाल उठाते और यह कहते सुने गए कि ''कोविड-19 के लिए एलोपैथिक दवाएं लेने से लाखों लोग की मौत हो गई।'' इस टिप्पणी का चिकित्सकों के संघ ने जोरदार विरोध किया, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उनसे ''बेहद दुर्भाग्यपूर्ण'' बयान वापस लेने के लिए कहा। एक दिन बाद, योग गुरु ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ''खुले पत्र'' में भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) से 25 प्रश्न पूछे। इसमें पूछा गया था कि क्या एलोपैथी ने उच्च रक्तचाप और टाइप -1 और टाइप-2 मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए स्थायी राहत प्रदान की है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)